

(13)

रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 1969 (चैत्र 29, 1891)

No. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1969 (CHAITRA 29, 1891)

इस भाग में सिम पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखा भारत का असाधारण राजपत्र 22 मार्च 1969 तक प्रकाशित किया गया है :—

The undermentioned Gazette of India Extraordinary was published up to the 22nd March 1969 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
32	No. F. 1. (65) B/68 dated 22nd. March, 1969.	Ministry of Finance.	Constitution of a team of officers mentioned therein to consider certain matters relating to Accounts & Budget Heads as recommended by the Administrative Reforms Commission in its report on "Finance, Accounts & Audit" and "The Machinery of the Government of India, and its procedures of work."
	सं० एफ० 1 (65)-बी/68 दिनांक 22 मार्च, 1969	वित्त मंत्रालय	प्रशासनिक सुधार आयोग की "वित्त लेखा और लेखा परीक्षक" और "भारत सरकार के तन्त्र और उसकी कार्य प्रणालियाँ" सम्बन्धी रिपोर्टों में की गई सिफारशों से पैदा होने वाले लेखा शीर्षकों और बजट शीर्षकों से सम्बद्ध कुछ मामलों पर विचार करने के लिए एक अधिकारी दल गठन करना।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

21G1/69

(347)

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ 347	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ 1341
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	419	भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिक नियम और आदेश ..	145
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	385
भाग I—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	349	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	147
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	49
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें ..	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	217
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1093	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	69
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	Page 473	पूरक संख्या 16—	
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	419	12 अप्रैल 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्टें	649
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence ..	—	22 मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	665
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence ..	349	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (II) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	Page 1341
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations ..	—	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	145
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills ..	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	385
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1093	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	147
		PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	49
		PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	217
		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	69
		SUPPLEMENT No. 16—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 12th April 1969 ..	649
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 22nd March 1969 ..	665

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

दिनांक 10 अप्रैल 1969

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1969

सं० 19-प्रेज/69—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम नाथ सिंह,
कांस्टेबल 4896,
“एफ” कम्पनी, 5वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री रामनाथ सिंह को मिजो पहाड़ियों में छिगछिप स्थित केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की 5वीं बटालियन की “एफ” कम्पनी में नियुक्त किया गया था। 11 नवम्बर, 1967 को सूचना मिली कि विद्रोहियों का एक दल रलदन गांव से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस चौकी पर आक्रमण करने के दरावे से बढ़ रहा था। रलदन से छिगछिप वाले मार्ग के दोनों ओर घात लगाई गई। श्री राम नाथ सिंह को घात-टुकड़ी में हल्की मशीनगन चालक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें विद्रोहियों को व्यस्त रखने तथा गोली चलाने का कार्य सौंपा गया था। लगभग 17-20 बजे 20 सशस्त्र विद्रोही दो दलों में घात-स्थान के समीप पहुंचे। घात-टुकड़ी के कमान्डर के आदेश पर श्री राम नाथ सिंह ने विद्रोहियों पर गोली चलाई, जिन्होंने जवाब में गोली चलाई और हल्की मशीनगन चौकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। विद्रोहियों में से एक श्री राम नाथ सिंह की ओर झपटा। श्री राम नाथ सिंह अविचलित रहे और अपनी निजी सुरक्षा की पूर्ण अवहेलना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चलाते रहे। श्री राम नाथ सिंह द्वारा प्रदर्शित सूक्ष्मबुद्धि और वीरता के कारण ही चार विद्रोही मारे गये और कुछ शस्त्र तथा गोला-बारूद बरामद किये गये।

श्री राम नाथ सिंह ने इस घात संक्रिया में उत्कृष्ट वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर, 1967 से दिया जायेगा।

सं० 20-प्रेज/69—आज तक संशोधित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 11-प्रेज/68, दिनांक 28 फरवरी, 1968 में प्रकाशित पूर्वता सारणी में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं:—

- (क) क्रम संख्या 8 में
जोड़ें “उपाध्यक्ष, योजना आयोग”
- (ख) क्रम संख्या 16 में
“योजना आयोग के सदस्य” से पूर्व “उपाध्यक्ष और” को हटा दें।
- (ग) क्रम संख्या 22 में
“मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली” के बाद से “महानगर परिषद” को हटा दें।
- (घ) क्रम संख्या 25 में
“कार्यकारी पार्षद, दिल्ली” के बाद से “महानगर परिषद” को हटा दें।
- (च) क्रम संख्या 29 में
“मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली” के बाद से “महानगर परिषद” को हटा दें।
- (छ) क्रम संख्या 30 में
“कार्यकारी पार्षद, दिल्ली” के बाद से “महानगर परिषद” को हटा दें।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1969

संकल्प

सं० एफ० 1-16/69-एस० डब्ल्यू०-3—भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 2-6/53 डी० 2 दिनांक 12 अगस्त, 1953 के अधीन समस्त देश में स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों को अपने वर्तमान कार्यक्रमों को बनाए रखने और उनका विकास करने तथा उन्हें सामान्य ढंग का बनाने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की तथा समय-समय पर उसके कार्यकाल को बढ़ाया और उसका पुनर्गठन किया, पिछली बार ऐसा 16 फरवरी 1968 से किया गया, देखिये समाज कल्याण विभाग का संकल्प संख्या एफ० 1-100/65-एस० डब्ल्यू०-3 (खण्ड II) दिनांक 15 फरवरी, 1968; तथा

क्योंकि भारत सरकार ने सतर्कता से विचार करके इसे 1 अप्रैल, 1969 से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन "केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड" के नाम से एक कम्पनी के रूप में रजिस्टर करने का निश्चय किया है;

इसलिए, भारत सरकार अब एतद्वारा यह आदेश देती है कि उसके उपरोक्त संकल्प दिनांक 12 अगस्त, 1953 के अधीन स्थापित किए गए उक्त समाज कल्याण बोर्ड को 31 मार्च, 1969 के उपरान्त से विघटित किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए:—

1. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
2. बोर्ड के सभी सदस्य।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. योजना आयोग।
5. राष्ट्रपति सचिवालय।
6. मंत्रीमंडल सचिवालय।
7. प्रधान मंत्री सचिवालय।
8. संसदीय मामलों का विभाग।
9. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
10. प्रेस सूचना ब्यूरो।
11. महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि को साधारण सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एस० रामदास, उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1969

सं० 61/3/68-पोल-1(ब)—निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (1950 का 4) के अधीन विभिन्न राज्यों में 31 दिसम्बर, 1968 को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या बनाने वाला निम्नलिखित विवरण सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है:—

31 दिसम्बर, 1968 को निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या

राज्य का नाम	भाग 3(I) (क) के अधीन निरुद्ध धारा				धारा 3(I) (ख) के अधीन महायोग	
	(I)	(II)	(III)	शीर्ष 2-4 तक का योग	निरुद्ध	
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—
2. आसाम	—	1,509	—	1,509	—	1,509
3. बिहार	—	5	—	5	—	5
4. गुजरात	—	—	—	—	—	—
5. केरल	—	—	1	1	—	1
6. मध्य प्रदेश	—	3	—	3	—	3
7. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
8. महाराष्ट्र	—	15	—	15	—	15
9. मैसूर	—	1	—	1	—	1
10. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
11. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
12. पंजाब	† 1	—	—	1	22	23
13. हरियाणा	—	—	—	—	—	—
14. राजस्थान	5	—	—	5	4	9
15. उत्तर प्रदेश	—	6	—	6	—	6
16. पश्चिम बंगाल	—	523	118	641	—	641
17. दिल्ली	3	—	—	3	3	6
18. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
19. गोआ, दमण व दियू	—	—	—	—	—	—
20. मनीपुर	—	—	—	—	—	—
21. त्रिपुरा	—	% 22	—	22	—	22
22. लक्काद्वीप, मिनिकोय तथा अमिनदिबी द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
24. दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
25. पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—
26. उपुसी	—	—	—	—	—	—
27. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
योग	9	2,084	119	2,212	29	2,241

यह व्यक्ति द्वारा 3(I) (क) (II) के अधीन भी नजरबन्द किया गया था।

% के व्यक्ति द्वारा 3(I) (क) (III) के अधीन भी नजरबन्द किये गये थे।

गोपी कृष्ण अरोड़ा, उप-सचिव

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1969

सं० 15/1/69-ए० आई० एस० (i)---निम्नलिखित सेवाओं में 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन-प्राप्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अफसरों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को चुनाव के द्वारा भरने के लिए अक्तूबर, 1969 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम सम्बन्धित मंत्रालयों की, और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की, सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं:—

- (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा,
- (ii) भारतीय विदेश सेवा,
- (iii) भारतीय पुलिस सेवा,
- (iv) केन्द्रीय सूचना सेवा, ग्रेड II श्रेणी I,
- (v) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,
- (vi) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा,
- (vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
- (viii) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I),
- (ix) भारतीय आर्इनैस फ़ैक्टरी सेवा, श्रेणी I (सहायक प्रबन्धक गैर-तकनीकी),
- (x) भारतीय डाक सेवा,
- (xi) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,
- (xii) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैण्ड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी I,
- (xiii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

- (xiv) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी II,
- (xv) केन्द्रीय सचिवालय, सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड श्रेणी II,
- (xvi) सीमा-शुल्क मूल्य-निरूपक (एग्जैक्टर) सेवा, श्रेणी II,
- (xvii) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा, श्रेणी II,
- (xviii) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख), अनुभाग अधिकारी ग्रेड II,
- (xix) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II, और
- (xx) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, क्लास II,
- (xxi) सैनिक भूमि मिलिटरी (लैण्ड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी II,
- (xxii) मनीपुर पुलिस सेवा, श्रेणी II,
- (xxiii) त्रिपुरा पुलिस सेवा, श्रेणी II,
- (xxiv) मनीपुर सिविल सेवा, श्रेणी II,
- (xxv) त्रिपुरा सिविल सेवा, श्रेणी II
- (xxvi) गोआ, दमन व दियू सिविल सेवा, श्रेणी II तथा
- (xxvii) पाण्डिचेरी सिविल सेवा, श्रेणी II।

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहता हो उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर दे। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी ऐसी सेवा में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जाएगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन-पत्र में नहीं करेंगे।

ध्यान दें (1):—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में उन सेवाओं के अधिमान-क्रम का

स्पष्ट उल्लेख करें जिनके लिए वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार जितनी सेवाओं का चाहें, उल्लेख करें जिससे नियुक्तियां करते समय, योग्यता क्रम में उनके स्थान को दृष्टि में रखते हुए, उनके अधिमानों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

ध्यान दें II :—उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र में मूलतः उल्लिखित सेवाओं में किसी अन्य सेवा का नाम जोड़ने अथवा उनके अधिमान-क्रम में कोई परिवर्तन करने से सम्बन्धित किसी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जो 31 दिसम्बर, 1969 को या उसके पूर्व आयोग के कार्यालय में नहीं प्राप्त हो जाता।

2. परीक्षा के परिणाम-स्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्धारित की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पद आरक्षित किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों में आदिम जातियों से अधिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1965 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 तथा संविधान तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. इन नियमों में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार वे सारे आपात्कालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जिन्हें प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् राज्यादेश प्राप्त हुआ था, और जो इस अधिसूचना की तारीख से पहले सन् 1969 के दौरान रिलीज हो चुके हों, या इसके पश्चात् सन् 1970 के अन्त तक रिलीज होने हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

यह व्यवस्था की जाती है कि प्रथम नवम्बर 1962 के पश्चात् सेना में भरती हुए आपात्कालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी/लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जो 1969 से पहले रिलीज हुए हों, वे नियम 8 की व्यवस्था के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 1 :—इन नियमों के उद्देश्य से “रिलीज” का तात्पर्य निम्नलिखित होगा :—

(i) आपात्कालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों से सम्बन्धित एक प्रावस्थाभाजित प्रोग्राम के अनुसार वास्तविक रिलीज,

(ii) लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में उनकी सेवा की अवधि समाप्त होने पर वास्तविक रिलीज,

(iii) सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता।

यह रिलीज सेना में सेवावधि की समाप्ति पर हुई हो, न कि प्रशिक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर, और वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को हिसाब में जाने के लिए स्वीकार किए गए लघु अवधि राज्यादेश के दौरान या उससे बाद में न हुई हों। दुर्व्यवहार या अदक्षता या अपनी ही प्रार्थना पर रिलीज हुए अधिकारियों के मामले इसके अधीन नहीं आते।

नोट 2 :—यदि प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात् किसी व्यक्ति को सेना में स्थायी राज्यादेश मिल जाए, या वह सेना से त्याग-पत्र दे दें, या दुर्व्यवहार, अदक्षता के कारण या अपनी ही प्रार्थना पर वह रिलीज हो जाए, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

नोट 3 :—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में नियुक्त इंजीनियर और डाक्टर, जिन्हें अनिवार्य सेवा योजना के आधीन कम-से-कम एक निर्धारित अवधि तक सेवा करनी ही होती है, और जिन्हें ऐसे सेवाकाल में सम्बन्धित नियमों के अधीन लघु अवधि राज्यादेश दिया जाता है, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 4 :—सेना के वालन्टीयर रिजर्व फ़ोर्स के वे अधिकारी, जो अस्थाई सेवा के लिए बुलाए गए हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

5. (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा या,

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूलरूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, खंका और पूर्वी अफ्रीका में किन्या, उगांडा, टेंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए, लेकिन नीचे लिखे

प्रकार के उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

- (i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गये हों और तब से आम तौर से भारत में रह रहे हों।
- (ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।
- (iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसके 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा द्वारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र देना होगा।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे।

परीक्षा में उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अंतिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार ने जिस वर्ष में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया उस वर्ष के अगस्त तक उसकी आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

यह व्यवस्था की जाती है कि निम्नलिखित नियम 9(ख) के अधीन इस परीक्षा में बैठने के हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने वाले उम्मीदवार को उल्लिखित तारीख को निम्नलिखित आयु का नहीं होना चाहिए।

- (i) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, उस वर्ष सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता।
इनके मामलों में 24 वर्ष।
- (ii) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह अगले वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता।
इनके मामलों में 23 वर्ष।

(iii) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे दूसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता।
इनके मामलों में 22 वर्ष।

(iv) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे तीसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता।
इनके मामलों में 21 वर्ष।

(v) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे चौथे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता।
इनके मामलों में 20 वर्ष।

(vi) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे पाँचवें वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता।
इनके मामलों में 19 वर्ष।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है :—

- (i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पाँच वर्ष,
- (ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,
- (iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,
- (iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,
- (v) यदि उम्मीदवार अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 3 नवम्बर 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

- (vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,
- (vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,
- (viii) यदि उम्मीदवार, कीन्या, उगांडा, या टैंगानिया (भूत-पूर्व टैंगानिका तथा अंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,
- (ix) यदि उम्मीदवार, 1 जून 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,
- (x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,
- (xi) रक्षा सेनाओं के उन विकलांग कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक वर्ष तक जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए।
- (xii) रक्षा सेवाओं के ऐसे विकलांग कर्मचारियों में अधिक से अधिक 8 वर्ष जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हैं तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए।
- (xiii) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो। वह यदि पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, उसके मामले में अधिक-से-अधिक तीन वर्ष। यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त प्रथम अवसर तक ही सीमित रहेगी।
- (xiv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, वह यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तथा साथ ही पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तो उसके मामले में अधिक-से-अधिक आठ वर्ष। यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्य अवसर तक ही सीमित रहेगी।
- (xv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया

है या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो वह यदि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह का निवासी है तो उसके मामले में अधिकतम चार वर्ष यह सुविधा राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले या 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में परीक्षा में बैठने के लिए मिलने वाले प्रथम अवसर तक ही सीमित होगी, तथा

- (xvi) यदि किसी उम्मीदवार ने राज्यादेश मिलने से पूर्व के प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या उसे 1963 अथवा 1964 व 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण की स्थिति में) राज्यादेश मिला हो, और भारतीय नागरिक हो तथा लंका से पुनर्वसित हो।

जो उम्मीदवार राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, या जिन्हें 1965 में (हुए राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, उनके सम्बन्ध में इस परीक्षा प्रथम अवसर के लिए ही सुविधा सीमित है।

नोट 1—नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (ii), (iii), (iv), (v) तथा (vi) में उल्लिखित उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (xiii) तथा (xiv) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

नोट 2—नियम 6 के परन्तुक के क्रम संख्या (iii), (iv), (v) तथा (vi) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (xv) तथा (xvi) के निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें 1963 में (हुए राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (xv) तथा (xvi) में निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 1964 के पश्चात् राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

उपर्युक्त परिस्थिति को छोड़ कर निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह प्रतिबन्ध 1966 में होने वाली परीक्षा से लागू होगा।

परन्तु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जाएगी जो उस वर्ष 1 अगस्त को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो। उपर्युक्त नियम 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उसके बाद के वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का ही हो गया था।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले चुका है।

8. इन नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत :—

- (1) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के पहले वाले की परीक्षा में बैठना चाहिए।
- (2) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके पहले वाले वर्ष की परीक्षाओं में बैठना चाहिए।

किन्तु शर्त यह है कि :

(क) जो उम्मीदवार सैन्य सेवा के कारण हुई अथवा बहु गर्ह विकलांगता के कारण अपांग हुआ है यह इस नियम के नीचे दिए हुए नोट में उल्लिखित अपवादों को छोड़ कर, 1969 में होने वाली परीक्षा में निम्नलिखित स्थितियों में बैठ सकता है,

- (i) यदि 1968 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित आखरी तारीख के बाद 1968 में अपंग हो गया हो या 1969 की परीक्षा के लिए आवेदन-पत्रों की निर्धारित आखरी तारीख के पहले 1969 में अपंग हो गया हो और यदि वह परीक्षा में एक बार बैठने का पात्र हो तो उसे परीक्षा में बैठने का केवल एक अवसर मिल सकता है,
- (ii) यदि 1968 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित आखरी तारीख के बाद 1968 में अपंग हो गया हो या 1969 की परीक्षा आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित आखरी तारीख के पहले अपंग हो गया हो तो और यदि वह परीक्षा में दो बार बैठने का केवल एक बार अवसर मिल सकता है,
- (iii) यदि 1967 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के निर्धारित आखरी तारीख के बाद 1967 या 1968 में अपंग हो गया हो या 1968 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित आखरी तारीख के पहले अपंग हो गया हो तो और यदि वह परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे परीक्षा में बैठने का दो बार अवसर मिल सकता है,
- (iv) यदि 1968 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित आखरी तारीख के बाद 1968 में अपंग हो गया हो तो और यदि क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार वह 1969 में सेवा में विमुक्त होने वाला था (आपातक राजादिष्ट अधिकारी होने की स्थिति में) या उसकी सेवा की अवधि की समाप्ति पर (अल्पकालीन सेवा राजादिष्ट अधिकारी होने की स्थिति में),

(ख) कमीशन द्वारा 1967 में होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए जिस उम्मीदवार की अनुमति दी गई थी किन्तु

जो सशस्त्र सेवाओं की सेवा की उपेक्षाओं के कारण उस परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह दो परीक्षा में दो-दो बार बैठने का पात्र होने पर 1969 में होने वाली परीक्षा में दूसरी बार बैठ सकता है।

(ग) 1968 की अवधि में या उससे पहले विमुक्त होने वाला जो उम्मीदवार नियम 9(ख) के अधीन परीक्षा में बैठना चाहता है वह परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र होने पर 1969 में होने वाली परीक्षा में दूसरी बार बैठ सकता है।

नोट 1—इस नियम के परन्तुक (क) में निहित उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जो 1967, 1968 और 1969 की अवधि में सैनिक सेवा के कारण या उससे होने वाली शारीरिक अयोग्यता के कारण अपंग हो गए और जो 1967, 1968 और 1969 में क्रमशः (आपातक राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार और (अल्पकालीन सेवा राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) सेवा की अवधि के अंत में विमुक्त किए जाने वाले थे।

नोट 2—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (i) और (ii) में निहित उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जो 1968 की अवधि में सैनिक सेवा के कारण या उससे होने वाली शारीरिक अयोग्यता के कारण अपंग हो गए और जो 1969 में (आपातक राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार और (अल्पकालीन सेवा राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) सेवा की अवधि के अन्त में विमुक्त हो जाने वाले थे।

नोट 3—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (III) में निहित उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जो 1968 की अवधि में सैनिक सेवा के कारण या उससे होने वाली शारीरिक अयोग्यता के कारण अपंग हो गए और जो 1967 में (आपातक राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार और (अल्पकालीन सेवा राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) सेवा की अवधि के अन्त में विमुक्त किए जाने वाले थे।

9. (क) उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में बताए गए किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट 1(क) में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी चाहिए,

बशर्ते कि—

(I) संघ लोक सेवा आयोग अपवादस्वरूप ऐसे उम्मीदवार को भी योग्यता प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास उपर बताई गई योग्यताएं नहीं हैं परन्तु जिसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जिनके स्तर से आयोग की राय में उसके परीक्षा में प्रवेश पाने का औचित्य प्रकट होता है।

(II) जो उम्मीदवार अन्यथा योग्यता प्राप्त है परन्तु जिसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित नहीं हैं, वह भी आयोग के पास आवेदन कर सकता है और आयोग के विवेक से उस परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में आपातक कमीशन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्ति के लिए सेवा चयन बोर्ड के सम्मुख

प्रस्तुत होने के समय, इस नियम के उप-नियम (क) में निर्धारित कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संस्था में अध्ययन कर रहा था, परन्तु जो सशस्त्र सेना में नियुक्त हो जाने के कारण अपना अध्ययन जारी नहीं रख सका और इस प्रकार ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं हुई, वह उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

नोट—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस नियम के उप-नियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएगा, परन्तु जिस परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले ही पूर्ण हो जाए। ऐसे उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, जो अन्यथा इसके लिए पात्र होंगे, परन्तु यह प्रवेश अस्थाई माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकेगा, यदि उक्त परीक्षा के उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण यथाशीघ्र और इस परीक्षा के आरम्भ होने के बाद किसी भी स्थिति में दो महीने तक प्रस्तुत नहीं करेंगे।

10. यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (II) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिए बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (III) में दी हुई है :—

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I,
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा,
3.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-II दिल्ली हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा, मनीपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन, दीउ सिविल सेवा, पांडी-चेरी सिविल सेवा, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा, मनीपुर पुलिस सेवा और त्रिपुरा पुलिस सेवा।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय, क्लास-I,

11. सशस्त्र सेवाओं में कार्य कर रहे उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपने यूनिट को कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दे, जो उसे संघ लोक सेवा के पास भेज देगा। उम्मीदवार जो स्वयं अपने यूनिट का समादिष्ट अधिकारी है, अपने से वरिष्ठ अधिकारी की मार्फत आवेदन-पत्र भेजे।

सरकारी सेवा में लगे अन्य सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध वाणिज्यिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाई की जा सकती है :—

(क) (I) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, तथा

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा, सरकार के अन्तर्गत नौकरियों से, उसको सजा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई हो सकती है।

16. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (Qualifying marks) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल आंकड़ों के आधार पर योग्यता-क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता-प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर

नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे, तो उसकी उस सेवा में, यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा।

18. (क) यदि परीक्षा फल के आधार पर, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जाएगा।

(ख) यदि अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक होगा, तो जो व्यक्ति नियुक्त नहीं हुए हैं उनके नामों को आगामी वर्ष (वर्षों) में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के नियतांश (quota) के अनुसार नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची (सूचियों) में रख दिया जाएगा।

19. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पताचार नहीं करेगा।

20. उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय जो अपना अधिमान-क्रम (Preference) बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

और बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (II) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (III) में उसी सेवा के सामने उल्लिखित सेवाओं के लिए ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिस सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I।
2.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-II, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा तथा दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाए। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की जिस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 12 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में इन मामलों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी।

23. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियों की जाती हैं, तब तक प्राप्त नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

24. भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हासत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

26. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उन के संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(नियम 9 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से नियमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा की गयी हो।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय

इंग्लैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैन्चेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सेट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कॉलेज)।

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।

ढाका विश्वविद्यालय।

सिंध विश्वविद्यालय।

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाण्डू।

परिशिष्ट I-क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदन योग्यताओं की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

1. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique)
2. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल काउंसिल ऑफ़ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
3. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा।
6. श्रीअरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।

7. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खान इंजीनियरी में डिप्लोमा।

[[8. मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपाधिपत्र यू० एस० एस० आर० में उच्च शैक्षिक स्थापना से अनुप्रमाणित उपाधि-गृहण बिना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबंध का पक्ष लिये हुए परन्तु राज्य की परीक्षाएं पास की हों।

परिशिष्ट II

परीक्षा की रूपरेखा

1. प्रतियोगिता-परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—

(क) तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है। इसके पूर्णांक 450 होंगे।

(ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा। इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना के सेवा-वृत्त के मूल्यांकन के लिए रखे जायेंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(i) निबंध	3 घंटे	150
(ii) सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	150
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	150

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही ली जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपयुक्त विषयों के लिए होंगे।

4(क) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (i) और (ii) के 'निबंध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिए जा सकते हैं; अर्थात् असमिया, बंगाल, गुजराती, हिन्दी कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू तथा उर्दू। अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप में किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिए चुनी होगी। विकल्प सम्पूर्ण पत्र के लिए लागू होगा न कि उस के किसी अंश के लिए।

(ख) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (ii) के सामान्य अंग्रेजी के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए।

टिप्पणी I— ऊपर दिए पैरा 4(क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न पत्र (ओ०) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 33 में संबंधित भाषा का नाम संबंधित प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के सामने देना चाहिए। यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न पत्रों के संबंध में कोई अंदराज नहीं किया जाता

है तो यह समझा जाएगा कि प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा। और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी II :— ऊपर दिए पैरा 4(क) में सविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे :—

भाषा	लिपि
1. असमिया	असमिया
2. बंगला	बंगला
3. गुजराती	गुजराती
4. हिन्दी	देवनागरी
5. कन्नड़	कन्नड़
6. कश्मीरी	फारसी
7. मलयालम	मलयालम
8. मराठी	देवनागरी
9. उड़िया	उड़िया
10. पंजाबी	गुरुमुखी
11. संस्कृत	देवनागरी
12. सिंधी	देवनागरी अथवा अरबी
13. तमिल	तमिल
14. तेलुगू	तेलुगू
15. उर्दू	फारसी

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक हीं होगी तो इस के लिये उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जायेंगे।

8. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसीलिए काट लिए जायेंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग—(क)

[परिशिष्ट II की धारा II की उप-धारा (क) के अनुसार]

1. निबंध—उम्मीदवारों से एक निबंध लिखने की अपेक्षा

की जाएगी। चुनाव के लिये कई विषय दिये जायेंगे। उनसे आशा की जायगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति की प्रशंसा दिया जायगा।

2. सामान्य अंग्रेजी—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जायेंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखकों दिए जायेंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. सामान्य ज्ञान—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि जिसने वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही होना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे :

भाग (ख)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप-धारा

(ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे। यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/ उनके लिये वह व्यक्तित्व की वृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि उनकी जांच तो लिखित प्रश्न-पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं

में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर बट रही है, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त व्यौरा :—

1. **भारतीय प्रशासनिक सेवा—**(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवार को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य, या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतनमान—

जूनियर—र० 400-400-500-40-700-कु० री०-30-1000 (18 वर्ष)

सीनियर—

(i) **समय-मान—**र० 900 (छठे या पहले)—50-1000-60-1600-50-1800 (22 वर्ष)

(ii) **सलेक्शन ग्रेड—**1800-100-2000

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन र० 2150 से र० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों को सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बितार्ह गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(ठ) **सचिव्य निधि—**भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (सचिव्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) **छुट्टी—**भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या—**भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय, सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ—**प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. **भारतीय विदेश सेवा—**(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कॉन्सुल बनाकर उन भारतीयों मिशनों में भेज दिया जायेगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जायेगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सबस्टेंटिव पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) वेतनमान—

जूनियर—र० 400-400-500-40-700-कु० री०-30-1000।

सीनियर—र० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50-1000-60-1500-50-1800।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन र० 1800 से र० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—र० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—र० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—र० 500 प्रति मास।

नोट—1. परखाधोन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

नोट—2. परखाधोन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

नोट—3. परिवीक्षाधीन के तौर पर यनयुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ० आर० 22-बी० (1) के अधीन दिया जाएगा।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय, विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बड़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इन्टरटेनमेंट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

- (i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान।
- (ii) सहायता प्राप्त डाक्टरों परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरों परिचर्या की सुविधाएं।
- (iii) भारत आने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक-से-अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जायेगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निवृत्त सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।
- (iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।
- (v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा/भत्ता।
- (vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Outfit Allowance) अधिकारी की सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है

जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम-से-कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए, छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, सम्मन्ध भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) **सेवा नियुक्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उद्धारकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. भारतीय पुलिस सेवा—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) }
(ग) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख), (ग)
(घ) } और (घ) में दिया गया है।

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) **वेतनमान :—**

जूनियर—र० 400-400-450-30-600-35-670-
कु० र०—35-950 (18 वर्ष)

सीनियर—र० 740 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100-
50/2-1250-50-1300 (22 वर्ष)

सलेक्शन ग्रेड—र० 1400

पुलिस उप-महानिरीक्षक—र० 1600-100-1800।

पुलिस कमिशनर, कलकत्ता और बम्बई—र० 1800-100-
2000।

पुलिस महानिरीक्षक—र० 2500-125/2-2750

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—र० 3000।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

- (छ) }
 (ज) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (छ),
 (झ) } (झ) और (ञ) में दिया गया है।
 (ञ) }

4. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्ति कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड)—1000 रु० स्थिर।

ग्रेड II—समय मान—350-25-500-30-590-द० अ०—30-800 रु०।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति ग्रेड II का न्यूनतम वेतन मान प्राप्त करना शुरू करेगा।

भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति के हकदार होंगे।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिणोषित केन्द्रीय वेतन मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अधिस्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहने के बड़े खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिए जायेंगे, यदि उन्हें ह्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिये य भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हृदायर्त अथवा बनाए जाने वाले विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले तदनु रूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-2 (श्रेणी-1)—

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (media organisation) में भारत भर में हैं। इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-एजेंसी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होता जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :

ग्रेड	वेतनमान
श्रेणी 1	
सलैक्शन ग्रेड	रु० 2500 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800-100-2000
(जूनियर मान)	रु० 1600-100-1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300-60-1600
(जूनियर मान)	रु० 1100-50-1400
ग्रेड II	रु० 400-400-450-30- 600-35-670-कु० रु०— 35-850।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350-25-500-30- 590-कु० रु०—30-800
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270-10-290-15- 410-कु० रु०—15-485।

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में सीधी भर्ती नीचे स्पष्ट की गई प्रतिशतता के अनुसार की जाती है :—

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम)	12½%
ग्रेड I	25%
ग्रेड II स्थायी पदों का	50%
ग्रेड IV	100%

ग्रेड III की रिक्तियां निम्नलिखित आधार पर बराबर के अनुपात में चयन द्वारा भरी जाती हैं :—

(i) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश, और

- (ii) ग्रेड IV की किसी झूटी पोस्ट अथवा अन्य किसी उच्चतर पद में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले अधिकारियों की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा।

ग्रेड II की 50% स्थायी तथा समस्त अस्थायी रिक्तियाँ, ग्रेड I की 75% रिक्तियों और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) की 87½% रिक्तियाँ तुरंत नीचे के ग्रेड में झूटी पोस्टों पर नियुक्ति अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरी जाती है।

सिलेक्शन ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम), तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियाँ सम्बन्धित ग्रेड से तुरन्त नीचे के ग्रेड में झूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाती हैं। यदि ऐसी पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो सिलेक्शन ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की ऐसी रिक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जायगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियों उक्त ग्रेड के कनिष्ठ वेतनक्रम में झूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

सरकार किसी भी ग्रेड में उस ग्रेड की संख्या के अधिक से अधिक 10% तक संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, ऐसी निश्चित की गई अवधि के लिए ओ 5 वर्ष से अधिक न होगी, राज्यों के प्रकार संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है। पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करते समय इस प्रकार भरे गये पदों को ध्यान में रख जाता है।

उक्त श्रेणियों की शेष रिक्तियाँ तथा चयन ग्रेड, सीनियर प्रशासन ग्रेड एवं ग्रेड-III की रिक्तियाँ भी तुरन्त निचली श्रेणियों में 'झूटी' पदों पर काम कर रहे अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके भरी जाती है। जूनियर प्रशासन ग्रेड के सीनियर वेतनमान की रिक्तियाँ उक्त ग्रेड के जूनियर वेतनमान में 'झूटी' पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों में से 'वरिष्ठता तथा 'सुयोग्यता' (सीनियरिटी-कमफिटनेस) के आधार पर पदोन्नति करके भरी जाती है।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परीक्षाधीन रहेंगे। परीक्षा-काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन) किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी। प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" (एंड-आफ-द-कोर्स-टेस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में भाषा-ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा से मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो।

(ii) परख-अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो उसे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परीक्षाधीनों को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षाधीनों का वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में ₹० 450 कर दिया जायगा। द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसका वेतन ₹० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। यदि कोई परीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम-संपूर्ति परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो पहले हो, रोक दिया जायगा।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायगा।

परीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा।

7. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा।

8. भारतीय रक्षा लेखा सेवा।

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने

(Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथा-स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथा-स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण अमन्तोषजनक रहा हो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना होगा/पड़ेगा।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है।

(च) वेतन मान—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा —
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान —

रु० 400-400-450-30-510-कु० रो०—
700-40-1100-50/2-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300-60-1600।

महालेखापाल—रु० 1800-100-2000-125-2250।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से

प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी। यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी।

नोट 4—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा :

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, रु० 400-400-450-30
क्लास I, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय -510-द० रो०-700
उत्पादन शुल्क, सहायक -40-1100-50/2-
कलक्टर, सीमाशुल्क। 1250।

डिप्टी कलक्टर, सीमा शुल्क डिप्टी रु० 1100-50-1300
कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क -60-1600।
अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट कलक्टर।

कलक्टर, सीमा शुल्क कलक्टर, रु० 1800-100-2000
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क -125-2250।

(क) नियुक्तियों 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की सम्भावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही “फील्ड सर्विस” भी करनी होगी।

नोट 1—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के समय-वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने 22-ख (1) की तारीख से मानेगा।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतन-मान में रु० 400 से अधिक वेतन तब नहीं दिया जायगा जब तक कि वह, समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती।

नोट 3—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा, श्रेणी I में नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

नोट 4—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा-शुल्क विभाग सादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनयादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जायगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे “पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा” उत्तीर्ण करनी होगी। उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी। पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर, रु० 450 कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जायगा। वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी “पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा” उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायगा।

नोट 5—परिवीक्षाधीन अधिकारियों का यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय मान—

रु० 400-400-450-480-कु० रो०-700-40-1100-1100-1150-1150-1200-1200-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300-60-1600।

रु० 1600-100-1800 (सलेक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1800-100-2000-125-2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—रु० 2750 (नियत)।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी।

उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रुपये से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन-वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

9. भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी I—(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(४) वेतन मान:—

आयकर अधिकारी. श्रेणी-I—

र० 400-400-450-30-510-रु० रो०-700-40-1100-50/2-1250 ।

आयकर सहायक आयुक्त—र० 1100-50-1300-60-1600 ।

आयकर आयुक्त—र० 1800-100-2000-125-2250 ।

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 480 कर दिया जायेगा। रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन-वृद्धि स्थगित कर दी जायगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भलिभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायगा और वह उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

10. भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (गैर-तकनीकी संवर्ग)

नियुक्तियां सहायक प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जायेंगी। उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा। इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

चुने हुए उम्मीदवारों को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को

सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद, कम-से-कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा।

सहायक प्रबन्धक, जिनका पुनरीक्षित वेतन-मान रु० 400-400-450-30-600-35-670-रु० रो०-35-950, गुणों (Merits) के आधार पर, भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

वेतन-मान	
1. उप-प्रबंधक (गैर-तकनीकी) उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी।	र० 700-40-1100-50/2-1250 ।
2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) सीनियर उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी।	र० 1100-50-1400
3. सहायक महानिदेशक आर्डनेंस फैक्टरी (ग्रेड 2)	र० 1300-60-1600
4. सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी (ग्रेड 1)	र० 1600-100-1800
5. उप-महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी।	र० 1800-100-2000

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समय-मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका निश्चय होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी, की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

11. भारतीय डाक सेवा

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आम तौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियाँ करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतन मानः—

समय-मान 400-400-450-30-510-कु० री०—
700-10-1100-50/2-1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक : 1303-60-1600।

महापोस्टमास्टर : रु० 1800-100-2000-125-2250।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड : रु० 2250-125/2-2750।
Senior Members, Post and Telegraph Board
Rs. 300.

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के परखाधीन अधिकारी रु० 400-400-450-30-480-510 कु० री०—700-40-1100-50/2-1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उस विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था, उसका वेतन मूल नियम 22 ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय समय पर उचित समझ जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जायगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे। चुने हुए उम्मीदवारों को, सरकार के निर्देशानुसार सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

12. भारतीय रेलवे सेवा —

(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं, पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा। सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियाँ हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो, हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊँची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों की देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परखावधि में पास कर लेनी चाहिये। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा अधिकारी के (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गये अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो भारतीय रेलवे सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उस की नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(झ) वेतन मान :

(क) जूनियर रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950 (प्राधिकृत-मान)।

सीनियर रु० 700 [छठे वर्ष या पहले-40-1100-50/2-1250 (प्राधिकृत मान)]

जूनियर प्रशासनिक-मानक 1300-60-1600 (प्राधिकृत-मान)

सीनियर प्रशासनिक-मान रु० 1800-100-2000-125-2250 (प्राधिकृत-मान)

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उस की वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी और परख-अवधि बढ़ा दी जायेगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा। तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की

तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जायेगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंही उसको रु० 400-950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्षों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उन की कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उस के बाद ही उन का वेतन समयमान में रु० 400 प्रति मास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

13. सैनिक भूमि और छावनी (सेवा श्रेणी I और श्रेणी II),

(क) नियुक्ति के लिये चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उस के कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

- (ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास नहीं होती तो सरकार अपने निर्णय में या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उस को परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।
- (iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उस की नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ती के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।
- (घ) यदि उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जायेगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस दे कर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।
- (ङ) इस सेवा के सदस्य को उस की परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जायेगी।
- (च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।
- (छ) वेतनमान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

- (i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1800-100-2000-125-2250
- (ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1600-100-1800।
- (iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1300-60-1600।

- (iv) सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1100-50-1400।

श्रेणी-I

- (v) उप-सहायक निदेशक, 400-400-450-
सैनिक भूमि और 30-510- रु०
छावनियां, सैनिक रु० 700-40-
संपदा अधिकारी और 1100-50/2-
कार्य-पालक अधिकारी 1250।

श्रेणी-II

- (vi) कार्यपालक अधिकारी 350-25-500-
30-509-रु० रु०
-30-800-रु० रु०
-830-35-900।
- (vii) सहायक सैनिक संपदा 350-25-500-30
अधिकारी -590-रु० रु०
-30-800 रु०
रु० -830-35-
900।

- (ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यता, उप-सहायक निदेशक, सैनिक संपदा अधिकारी, श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उप-धारा—(4) के खण्ड (ड) का उप खण्ड (1) लागू होता है।
- (ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यता, उन छावनियों में नियुक्त किया जायेगा। जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

- (झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (by selection) की जायेंगी [विरियता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जायेगा जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी II से श्रेणी I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

- (ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I से तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

- (ञ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी।

- (ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से सम्बन्धित न हो।
- (ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत से किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ड) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायेगी तो उसके अनुसार, परख की कुछ अवधि भी बढ़ जायेगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकम में वापस करनी होगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जायेंगी। जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएँ पास कर ली हों। ध्यान रहे किये परीक्षाएँ नियमितः प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जाय। क्योंकि विषेश (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उनकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अन्तिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी। जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएँ पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियां ली जा सकेंगी।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही परख-अवधि

में पास कर लेनी चाहिये। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

- (i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और
- (ii) समय समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा। वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(छ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी।

(ज) अधिकारियों को, आम तौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे। और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सकें।

(झ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की अपेक्षित वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आम-तौर पर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (Order of merit) के अनुसार निश्चित की जायेगी यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी। वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है। उसको यह भी अधिकार है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है।

(ड) वेतन मान :—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670-
कु० रु०—35-950 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40-1100-50/2-1250 (प्राधिकृत मान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300-60-1600 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1800-100-2000-125-2250 (प्राधिकृत मान)।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी। और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकारी अपने परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्षों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, वित्तियमित कर दिया जायेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उससे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनको नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और वित्तियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

(ट) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी।

(ड) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति (Establishment) स्थापना में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्ण-रूप से चुनाव (Selection) के आधार पर ही की जायेंगी। एकमात्र बरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये वादा नहीं किया जा सकता।

(ड) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इसमें महाप्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए।

नोट 4—प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी को गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिये यात्रा करनी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिए किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है। इस सब के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है।

पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष

मद	अवधि
1. राष्ट्रीय-प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी	4 महीने
2. बड़ौदा स्टाफ कालिज (प्रथम प्रावस्था)	3 "
3. क्षेत्रीय स्कूल, रक्षक के कर्तव्य सीखने के लिए	1 "
4. रक्षक के रूप में कार्य करते हुए	3 1/2 "
5. बुकिंग पार्सल आफिस, राइस रोड तथा यानांतरण रोड	1 "
6. यातायात खाते तथा खातों का याजिक निरीक्षक	1 1/2 "
7. क्षेत्रीय स्कूल में सहायक स्टेशन मास्टर की अर्हता प्राप्त करने के लिए	1 "

पद	अवधि
8. गार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गार्ड फोरमैन तथा ट्रेन ऐग्जाभिनर के रूप में कार्य	3 महीने
9. ऐसिस्टेंट लोको फोरमैन के रूप में कार्य	½ "
10. सहायक नियंत्रक के रूप में कार्य	2 "
11. (क) क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण	1 "
(ख) विद्युत नियंत्रक का प्रशिक्षण	½ "
12. बड़ौदा स्टाफ कालिज (द्वितीय प्रावस्था)	1½ "
13. कार्यालय पूर्वी रेलवे मुख्यालय (संचालन)	1½ "
14. कार्यालय, पूर्वी रेलवे मुख्यालय (वाणिज्य)	1½ "
	23½ "
प्रशिक्षण के विभिन्न पदों के लिए ज्वाइनिंग टाईम तथा अनिवार्य छुट्टी के लिये सुरक्षित रखी गयी समयावधि	½ "
	24 "

टिप्पणी : 3 से 11 तक मर्वे जिन का समय 1 वर्ष होगा आसनसोल डिबीजन में होंगी ।

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जायेगा । परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी ।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतंत्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाये और योग्य घोषित किया जाये ।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800
ग्रेड-I अवर सचिव	रु० 900-50-1200
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I	रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-30-830-35-900 ।
सहायक ग्रेड	रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 ।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं ।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख-अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएँ पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊँचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे ।

(ज) जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे ।

16. सीमा शुल्क मूल्यांकन सेवा, क्लास II

(क) मूल्यांकन ग्रेड में रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-830-35-900 के वेतनमान में भरती की जाती है । नियुक्तियाँ दो वर्ष के लिये परीक्षा के आधार पर की जाती हैं तथा परीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो, बढ़ा भी सकता है । परीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । उन्हें रु० 375 से ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते ।

(ख) यदि परीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियुक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है।

(ग) परीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबंधित ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जायेगा।

(घ) मूल्यांकक की हैसियत से पांच वर्ष सेवा कर लेने के बाद उम्मीदवार मुख्य मूल्यांकक (Principal Appraiser) के अगले उच्च ग्रेड (रु० 600-35-950) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे। उसके बाद वे महायुक्त कलेक्टर के अगले उच्च ग्रेड (रु० 400-1250) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे।

(ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे। जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास II, की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी। इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी समान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

17. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा श्रेणी-II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकेगी। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पत्रका कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवावृत्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतन मान :—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड) रु० 900-50-1250।

ग्रेड II समय-मान रु० 400-25-500-30-590-
द० अ०-30-800-द० अ०-
30-830-35-900।

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति आरम्भ में ग्रेड II के सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतन-मान वाले पदों के लिए पदोन्नति के हकदार होंगे।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिणोदित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिये ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाले हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनु रूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

18. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

सेवा	वेतनमान
(i) सहायक निदेशक अवर सचिव	रु० 900-50-1250
(ii) अनुभाग अधिकारी	रु० 350-25-500-30- 590-कु० रो०-30- 800-कु० रो०-30- 830-35-900।
(iii) सहायक	रु० 210-10-270-15- 300-कु० रो०-15- 450-कु० रो०-20- 530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी की सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनकी सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक, अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket orders) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी)।

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिवान कर सकेंगे।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नहीं दिल्ली में हैं।

19. मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास-II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतन मान—

₹ 300-25-450—₹ 400—30-600—₹ 400—30-900।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर पुलिस सेवा नियमावली, 1965 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे।

20. त्रिपुरा पुलिस सेवा क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा। यदि प्रशासक की राय में

उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान—

₹ 300-30-510—₹ १०—30-750—₹ १०—30-900।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा पुलिस सेवा नियमावली, 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे।

21. मणिपुर सिविल सेवा क्लास II

(क) नियुक्तियाँ दो वर्ष की परीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है, तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—₹ 1000-40-1200।

ग्रेड II—₹ 350-30-500—₹ १०—30-650—₹ १०—35-1000।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर सिविल सेवा नियमावली, 1965, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे।

22. त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियाँ दो वर्ष की परीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—₹ 1,175/ (नियत)।

ग्रेड II (समय वेतन-मान)—₹ 325-30-475
35-545—₹ १०—35-825—₹ १०—35-1000।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

23. गोआ, दमन तथा दियू सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियाँ दो वर्ष की परीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोआ, दमन तथा दियू संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिबीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उस से यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिबीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिबीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियू संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ड) वेतनमान :—

ग्रेड I (चयन ग्रेड) — रु० 700-40-1100-50/2-1250

ग्रेड II — रु० 350-25-500-30-590-द० रो० 30-800-रु० रो०-30-830-35-900

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन, तथा दियू सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

24. पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिबीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिबीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिबीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिबीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिबीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिबीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ड) वेतनमान :—

ग्रेड I रु० 375-25-800

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

25. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, अधीक्षक ग्रेड श्रेणी II

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में फिलहाल निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी	1100-50-1400 रु०
सिविलिया स्टाफ अधिकारी	740-30-800-50-1150 रु०
अधीक्षक ग्रेड	350-25-500-30-590-द० रो०-30-800 रु०
सहायक ग्रेड	210-10-270-15-300-द० अ०-15-450-द० अ०-20-530 रु०।

उपरोक्त सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतरसेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है।

सीधी भर्ती केवल अधीक्षक ग्रेड तथा सहायक ग्रेड में ही की जाती है।

(ख) अधीक्षक ग्रेड 2 वर्ष तक परिबीक्षा पर रहेंगे। इन अवधि के दौरान उन्हें ऐसे कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा परीक्षाएं पास करनी पड़ सकती हैं जिन की सरकार व्यवस्था करे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न होने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिबीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जाएगा।

(ग) परिबीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो सम्बन्धित अधिकारी को उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार के विचार में संतोषजनक न रहा हो तो चाहे तो उसे सेवा से निकाल दे या परिबीक्षा की अवधि को उतने काल तक के लिये बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियाँ करने का अधिकार सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाय तो वह अधिकारी उपरोक्त धाराओं में बरिगंत सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है।

(ङ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा विभाग के अन्तर सेवा संगठनों में अधीक्षक सामान्यतः 'अनुभागों' मुखिया होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या एकाधिक अनुभागों का कार्यभार सम्हालेंगे।

(च) अधीक्षक समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के हकदार होंगे।

(छ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सेवा के बरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हकदार होंगे।

(ज) जहाँ तक छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है उनका नियंत्रण सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी समय-समय पर प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये लागू विनियमों तथा आदेशों द्वारा होगा।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

टिप्पणी-1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इसलिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका शारीरिक स्तर अपेक्षित स्तर तक का है। इन अधिनियमों का यह भी ध्येय है कि स्वास्थ्य परीक्षकों को ऐसे उम्मीदवारों को जो अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा अयोग्य घोषित न हो जाए मार्ग दर्शा सकें। तथापि, यह जानसे हुए कि उम्मीदवार इन अधिनियमों में दी हुई शर्तों के अनुसार अयोग्य नहीं है स्वास्थ्य बोर्ड को आज्ञा होगी कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कारण लिख कर सिफारिश करें जिस से वह बिना असुविधा के सेवा में भर्ती किया जा सकता है।

2. तथापि, यह भी स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार को किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो पांच के लिए

उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा अतकनीकी" के अधीन इस प्रकार से होगा :—

क—तकनीकी

(1) रेलवे इंजीनियरी सेवा (सिविल, विद्युत यांत्रिक तथा सिग्नल) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस, और समुद्री विभाग के पद।

(2) केन्द्रीय इंजीनियरी श्रेणी I और II, तार इंजीनियरी श्रेणी I, विद्युत इंजीनियरी वर्ग I और II, भारत सर्वेक्षण, श्रेणी I और II समुद्रपार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पद पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के निरीक्षण स्कंध के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी।

(3) भारतीय वन सेवा।

(4) भारतीय पुलिस सेवा।

ख—अतकनीकी

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० और ए० एस०, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे भंडार सेवा, रेलवे सुरक्षा दल। रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी I और II और रेलवे में श्रेणी I और II के सभी अन्य पद भारतीय रक्षा लेखा सेवा, आयकर अधिकारी (श्रेणी I, ग्रेड II और श्रेणी II) सेवा, भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी I और II, भारत भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग श्रेणी I और II, बेतार योजना तथा समन्वय संगठन के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

कद	छाती का घेर	फैलाव
	(पूरा	
	फैला	
	कर)	

से० मी० से० मी० से० मी०

1. रेलवे इंजीनियरी सेवा सिविल, विद्युत, यांत्रिक तथा सिग्नल परिवहन (याता यात तथा वाणिज्य विभागों) रेलवे सुरक्षा दल और विभागों के पदों पर और समुद्र-पार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पदों में

(पुरुषों के लिए)	152	84	5
(स्त्रियों के लिए)	150	79	5
2. भारतीय पुलिस सेवा—			
(पुरुषों के लिए)	165	84	5
(स्त्रियों के लिए)	150	79	5
3. भारतीय वन सेवा—			
(पुरुषों के लिए)	163	84	5
(स्त्रियों के लिए)	150	79	5

“गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी जिनकी औसत कद की लम्बाई दूसरों से छोटी होती है।”

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा:—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़ें सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिछलियां, नितंब और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है:—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89, 86-93.5 आदि नाम को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से भिन्न फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा:—

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक-इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा:

सेवा की श्रेणी	दूर की नजर	नजदीक की नजर
	अच्छी खराब	अच्छी खराब
	आंख आंख	आंख आंख
	(ठीक की हुई दृष्टि)	(ठीक की हुई दृष्टि)

वर्ग I और II

(I) तकनीकी 6/6 6/2 जे० 1 जे० 2
या

(II) प्रतकनीकी 6/9 6/12 जे० 1 जे० 2

(घ) आयोगिता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिये और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिये। व्याधिकृत दृष्टा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) दृष्टिक्षेत्र—सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फ्रेंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि-क्षेत्र को परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(च) रतौंधी (माइड ब्लाइंडनेस)—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन “ए” की कमी होने के कारण और (2) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेंटोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन “ए” के खाने से ठीक हो जाता है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस में खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपयुक्त (1) और (2) दोनों के लिये अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा। उपयुक्त (2) के लिये विशेषतया जब फंडस खराब न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की आ-

व्ययकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटिनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिये साधारण चिकित्सक जांच के लिये यह समय नहीं है। अतः तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय। विभाग को चाहिये कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह बात इस बात पर निर्भर होगा कि पद से सम्बन्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली उनकी ड्यूटी जिस तरह की होगी।

- (ठ) कलर विजन—उम्मीदवारों को स्वास्थ्य परीक्षा के लिये सम्बन्धित मंत्रालय। विभाग को भेजते समय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को यह सूचना देनी होगी कि उम्मीदवार तकनीकी सेवा के लिये है (जिस में क्षेत्र सेवा भी शामिल है) और कलर विजन परीक्षा की आवश्यकता है या अतः तकनीकी सेवा के लिये है और कलर विजन परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सभी तकनीकी सेवाओं में कलर विजन परीक्षा आवश्यक नहीं हो सकती है और सम्योद्धित मंत्रालय। विभाग को यह निर्णय करना होगा और स्वास्थ्य परीक्षा के समय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को सूचित करना होगा। रेलवे मेडिकल और सुरक्षा दल सेवा में नियुक्त होने वाले वर्ग I और वर्ग II के सभी उम्मीदवारों को कलर विजन जांच में पास होना आवश्यक है।

- (ज) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन्स)---

- (i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन ट्राट (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिस के परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिये।
- (ii) भ्रंशपन (रिफ्रेक्ट)---तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनोकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भ्रंशपन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिये। यह रेलवे सुरक्षा दल के उम्मीदवारों के लिये भी लागू होगा। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भ्रंशपन को अन्य सेवाओं के लिये अयोग्यता के कारण नहीं समझना चाहिये।
- (iii) एक आंख वाले व्यक्ति---एक आंख का साधारण प्रभाव यह होता है कि यह स्ट्रेओस्कोपिक विजन या ग्रहण शक्ति की गहराई पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार की नजर (बहुत से सिविल पदों के लिये आवश्यक नहीं है। इस लिये स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड ऐसे एक आंख

वाले व्यक्तियों को सिफारिश कर सकता है जिन के लिये उसे संतोष है कि वह सब कार्यों को कर सकता है जिस विशेष नौकरी के लिये वह उम्मीदवार है यद्यपि उस की काम करने वाली आंख की दृष्टि पकड़ 6/6 दूर की नजर के लिये और 0-6 नजदीक की नजर के लिये हो और वर्तन ट्राट (रिफ्रेक्टिव एरर) 4-00 डी० से कम या अधिक न हो।

(2) कोन्टैक्ट लेंस (Contact Lenses) :

उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टैक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिये टाइप किए हुए अक्षर 16 फुट से प्रकाशित हों।

(7) ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

- (i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+ आयु होता है।

- (ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाये। यह तरीका विष्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टोलिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टोलिक प्रेशर को सदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (ऑर्गेनिक बीमारी) है, [ऐसे सभी केसों में हृदय की एकसरे और विद्युत हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकाल (लोयरेस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार को योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।]

ब्लड प्रेशर (रक्तदाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीज की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फीताकर

समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूँढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 m.m. Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टोलिक प्रेशर दर्शाती है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डाय-स्टोलिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कपल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबीटीज) के छोटक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसुरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधु मेही (नानडाय-बेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निदिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेषण करना चाहिए

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई विह्वल है या

नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो, इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

- (ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।
- (ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।)
- (घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।
- (ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।
- (च) उसे रफचर (हार्निया या फटन) है या नहीं।
- (छ) उसे हाइड्रोसील, बड़ी हुई बरिकोसील शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।
- (ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पंरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।
- (झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।
- (ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।
- (ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।
- (ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।
- (ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण इयूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली-जुसी प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, उनके लिए ऊपर पंरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवारों को अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपिलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किए जाएंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जप्त कर ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चाहें तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए।

अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जानेवाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक-भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय या स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य-परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह-मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (आपाइंटिंग अथॉरिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को ठेकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये, कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टर बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टर बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत व्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टर बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है

वहां डाक्टर बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो एक दूसरे डाक्टर बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम-से-कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिये। मिश्रित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिये।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिये गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

1. अपना पूरा नाम लिखें.....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असली, नागालैंड आदिम जातियों आदि से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसेनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित व्योरा दें।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण
---	--

आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण	कद (जूते उतार कर).....वजन..... अत्युत्तम वजन.....कब था?..... वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन..... तापमान..... छाती का घेर..... (1) पूरा सांस खींचने पर..... (2) पूरा सांस निकालने पर..... 2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी..... 3. नेत्र..... (1) कोई बीमारी..... (2) रतोंधी..... (3) शलर विजन का दोष..... (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन)..... (5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी).....
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	
आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण	

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?	8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए कितल सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?	9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?	10. कब और कहाँ मेडिकल बोर्ड हुआ?	11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।
मैं घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।				
उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....				
मेरे सामने हस्ताक्षर किए।				
बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर.....				
नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार- जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्ति हो भी जाये तो बाध्यत्व निवृत्ति भत्ता [सुपरएनुएशन अलाउंस या उपदान (ग्रेचुअटी)] के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।				
(ख)की शारीरिक परीक्षा की/ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट				
1. सामान्य विकास : अच्छा.....बीच का.....कम पोषण : पतला.....औसत.....मोटा.....				

दृष्टि की पकड़ चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर
		गोल सिलि० अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०	
	बा० ने०	
पास की नजर	दा० ने०	
	बा० ने०	
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०	
	बा० ने०	
4. कान : निरीक्षण.....सुनना		
दायां कान.....बायां कान.....		
5. ग्रंथियांथाइराइड.....		
6. दांतों की हालत.....		
7. श्वसन तंत्र (रस्पिरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें।		
8. परिसंचरण तंत्र (सर्कुलेटरी सिस्टम)		
(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ?		
.....		
गति रेट :		
खड़े होने पर :		
25 बार कुदाए जाने के बाद.....		
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद.....		
(ख) ब्लड प्रेशर.....सिस्टोलिक.....डायस्टोलिक		
.....		
9. उदर (पेट) : घेर.....दाव वेदना (टेंडरनेस) हानिथा.....		

- (क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर.....तिली...
गुर्दे.....ट्यूबर.....
- (ख) बवासीर के मस्से.....फिस्चुला.....
10. तांत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत.....
11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता.....
12. जनन-मूल तंत्र (जनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसिल, बैरिक्वोसील आदि का कोई संकेत। मूल परीक्षा :
- (क) कैसा दिखाई पड़ता है
- (ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)
- (ग) एलव्युमेन
- (घ) शक्कर
- (ङ) कास्ट
- (च) कोणिकाएं (सेल्स)
13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्टें
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है ?
15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—
- (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।
- (ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा, मनीपुर पुलिस सेवा तथा त्रिपुरा पुलिस सेवा.....
- (ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I और II मणिपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा.....
- (ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—
- (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।
- (ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नज़र, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।
- (ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नज़र, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।
- (घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II
- (iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है।

नोट—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये।

- (i) योग्य (फिट)
- (ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण.....
- (iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण.....
- स्थान.....अध्यक्ष (प्रेसिडेंट).....
- तारीख.....सदस्य.....
- सदस्य.....

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 मार्च 1969

संकल्प

सं० 25(1)/68-ओ० आर०—आसाम में एक उपयुक्त स्थान पर एक और तेल शोधनशाला की स्थापना की तकनीकी आर्थिक सम्भावनाओं का अध्ययन करने तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, भारत सरकार ने निम्न व्यक्तियों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है:—

- (1) श्री बी० एस० नेगी, सदस्य (अन्वेषण) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संयोजक)
- (2) डा० हरि नारायण, निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकी गवेषणा संस्था
- (3) डा० एम० जी० कृष्णन, निदेशक, पेट्रोलियम की भारतीय संस्था
- (4) डा० ए० के० घोष, आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड।
- (5) श्री एस० डी० भाम्शरी, महा-प्रबन्धक, भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग)।

II. विशेषज्ञ-समिति निम्न विषयों का अध्ययन करेगी तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:—

- (1) आसाम में कच्चे तेल से संसाधन, विभिन्न तेल क्षेत्रों से उत्पादन की वार्षिक दर तथा तेल की मात्वाएं (जो दिग्बोर्ड, गोहाटी और बरौनी में अधिकतम रूपांकन क्षमताओं पर चालित वर्तमान शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने के बाद उपलब्ध हो सकेंगी।
- (2) आसाम राज्य में इस समय तथा भविष्य में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग की किस्म तथा सीमा और अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री के लिए आर्थिक वितरण के क्षेत्र।
- (3) उपलब्ध या प्रस्तावित परिवहन के साधनों पर भी विचार करते हुए एक नई शोधनशाला की स्थापना या एक अथवा अधिक वर्तमान संयंत्रों के विस्तार की तकनीकी-आर्थिक साम्भाव्यता तथा तुलनात्मक मितव्ययता।

- (4) अन्य सम्बद्ध मामले, जिनका आसाम में अतिरिक्त शोधन क्षमता की स्थापना से सम्बन्ध हो।

III. समिति इस विषय पर आसाम सरकार तथा अन्य व्यक्तियों आदि के विचारों पर भी विचार करगी। समिति तीन महीनों की अवधि में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

माधव राजवाडे, संयुक्त सचिव

**प्रौद्योगिक विकास, प्रान्तरिक व्यापार तथा समन्वय-कार्य मंत्रालय
(प्रौद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1969

संकल्प

सं० 28-17/68-एच० ई० सी० एच० ई०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 28-2/66-एच० ई० सी० एच० ई०, दिनांक 28 मार्च, 1967 के सन्दर्भ में विद्युत ज्योति, भोपाल के अनुसंधान तथा विकास संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा करने और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बारे में परामर्श देने हेतु एक समिति का गठन करने के सम्बन्ध में है।

2. चूंकि श्री के० सी० लाल नेहरो इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के अध्यक्ष पद का कार्यभार छोड़ दिया है, अतः यह उपरिलिखित समिति के सदस्य नहीं रहे।

3. श्री ओ० एस० मूर्ति, अध्यक्ष, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को श्री डी० सी० बैजल के स्थान पर जिन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के अध्यक्ष के पद का कार्यभार अब छोड़ दिया है, उपरिलिखित समिति का तत्काल से सदस्य नामित किया जाता है। श्री ओ० एस० मूर्ति के विकल्प में श्री बी० कृष्णामूर्ति के स्थान पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के आयोजन और विकास प्रमुख श्री एच० सी० केसकर होंगे।

प्रादेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाये तथा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

कृष्णदेव नारायण सिंह, संयुक्त सचिव

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)**

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1969

सं० 28(1)/67-समन्वय(1)—कृषि अर्थ शास्त्र अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, के निदेशक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि अर्थ शास्त्र, सांख्यिकीय एवं विपणन अनुसंधान हेतु स्थायी समिति के सदस्य—डा० एस० सी० गुप्त ने 1 अगस्त, 1968 से संयुक्तराष्ट्र के कृषि

व खाद्य संगठन में पद ग्रहण कर लिया है। अतः परिषद् की नियमावली के नियम 11 (ए) व नियम 77 की व्यवस्थाओं के अनुसार वह अब परिषद् की कृषि अर्थ शास्त्र, सांख्यिकीय एवं विपणन अनुसंधान की स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 5 अप्रैल 1969

सं० 30(3)/69-समन्वय(1)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34(V) के अन्तर्गत श्री जी० ए० अप्पन, सदस्य राज्य सभा, 11-बी, एल्डम्स रोड, परिषद् के अध्यक्ष (खाद्य व कृषि मंत्री) द्वारा 24 मार्च, 1969 से तीन वर्ष के लिए अथवा जब तक वह सोसाइटी के सदस्य बने रहें—जो भी अवधि पहले समाप्त हो—सोसाइटी की शासी निकाय के सदस्य चुन लिये गये हैं।

सं० 29(1)/67-समन्वय(1)—डा० एम० के० मुखर्जी, उप-कुलपति, कल्याणी विश्वविद्यालय, पोस्ट कल्याणी, जिला नाडिया, पं० वंगाल, एतद् द्वारा प्रो० बी० एम० दान्डेकर (जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है) के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 24 मार्च, 1969 से 30 जुलाई, 1969 तक, अथवा जब तक समिति में इनका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये—इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि शिक्षा की स्थायी समिति के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

एम० अहमद, उप-सचिव

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1969

संकल्प

सं० 16-24/66-प्रशि०—राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान नवम्बर, 1965 से इस मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली पूर्ण वित्तीय सहायता से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

2. कुछ समय से राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान के कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 98वीं रिपोर्ट में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया था कि एक स्वतंत्र दल द्वारा संस्थान के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाए और इस बारे में वर्तमान कार्यक्रमों को जारी रखने अथवा उनमें संशोधन करने के प्रश्न की जांच की जाए ताकि उन्हें अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा याथार्थिक बनाया जा सके।

3. तदनुसार, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए एक दल स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

4. दल का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(1) प्रो० एम० बी० माथुर, भूतपूर्व उप-अध्यक्ष कुलपति, जयपुर विश्वविद्यालय तथा इस समय निदेशक, एशियन इंस्टीच्यूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली ।

(2) श्री पी० एस० बापना, अध्यक्ष-एवं-सदस्य प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, भोपाल ।

(3) डा० रवि जे० मथाई, निदेशक, इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ मेनेजमेन्ट, अहमदाबाद ।

5. श्री यू० सी० गिलदयाल, निदेशक (प्रशिक्षण), राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद दल के गैर-सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

6. मूल्यांकन दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना; और

(2) वर्तमान कार्यक्रमों को जारी रखने अथवा उनमें संशोधन करने के प्रश्न की जांच करना, ताकि उन्हें और अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा याथार्थिक बनाया जा सके ।

7. दल को अपनी रिपोर्ट छः महीनों के भीतर देनी चाहिए । दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति दल के सभी सदस्यों, शाखाध्यक्ष, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद तथा श्री यू० सी० गिलदयाल, निदेशक (प्रशिक्षण), राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद को भेजा जाए ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 5 अप्रैल 1969

संकल्प

सं० 5/1/66-पी० आर०—मंत्रालय को पंचायती राज के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त नीतियों के बारे में सलाह देने के लिए इस विषय के विभिन्न तथ्यवेत्ताओं के एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है । भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) ने अपने 12 मई, 1964 के संकल्प संख्या 14/3/64-पी० आर० द्वारा पंचायती राज सम्बन्धी सलाहकार परिषद की स्थापना की थी । इसका कार्यकाल 12 मई, 1966 को समाप्त हुआ था ।

2. अब इसके द्वारा परिषद का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता है :—

(1) अध्यक्ष . केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री ।

(2) उपाध्यक्ष . खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री ।

(3) सदस्य

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय उप-मंत्री ।

(2) पंचायती राज मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।

(3) सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकारिता मंत्री असम सरकार, शिलांग ।

(4) पंचायती राज के प्रभारी मंत्री, बिहार सरकार, पटना ।

(5) पशु-पालन, सा० वि० तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के उप-मंत्री, जम्मू तथा काश्मीर सरकार ।

(6) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

(7) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।

(8) पंचायत तथा सामुदायिक विकास मंत्री, केरल सरकार, त्रिवेंद्रम ।

(9) स्थानीय प्रशासन मंत्री, तमिल नाडू सरकार, मद्रास ।

(10) विकास तथा सहकारिता मंत्री, मैसूर सरकार, बंगलौर ।

(11) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।

(12) स्थानीय स्वायत्त शासन (ग्रामीण) तथा पंचायती राज राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।

(13) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।

(14) पंचायती राज के प्रभारी मंत्री, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ ।

(15) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

(16) पंचायती राज के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

(17) पंचायती राज के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।

(18) पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।

- (19) लुंसांग कार्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री, नागालैण्ड सरकार, कोहिमा।
- (20) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी योजना आयोग के सदस्य।
- (21) प्रधान, अखिल भारतीय पंचायत परिषद्।
- (22) अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
- (23) श्री टी० एन० सिंह, संसद सदस्य, 16-अशोक रोड, नई दिल्ली।
- (24) श्री साहिक अली, संसद सदस्य, 31, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- (25) श्री जी० एस० रेड्डी, संसद सदस्य, 135, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
- (26) श्री रामकृष्ण सिन्हा, संसद सदस्य, 38-मीना बाग, नई दिल्ली।
- (27) श्री शशि भूषण, संसद सदस्य, 7-नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
- (28) श्री विष्वनारायण शास्त्री, संसद सदस्य, 202-साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली।
- (29) श्री एम०वाई० घोरपदे, एम० एल० ए०, मैसूर।
- (30) प्रो० एम० बी० माथुर, भूतपूर्व उप-कुलपति, राजस्थान, विश्व-विद्यालय, जयपुर।
- (31) श्री बी० आर राधाकृष्णन, नं० 1, थिरुवेलूर, कोयल स्ट्रीट, मिलापुर, मद्रास।
- (32) श्री नेतर पी० बामोवरन, कोचू थोपे, हवाई अड्डे के निकट, त्रिवंद्रम, केरल।
- (33) श्री बी० पी० नागराजमूर्ति, रागीबोमनाहल्ली, मालावल्ली तालुक, मंड्या जिला, मैसूर राज्य।
- (34) प्रो० बी० एम० डांडेकर, गोखले इंस्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स एण्ड इकनामिक्स, पूना।
- (35) श्रीमती मायादेवी चेट्टी, करसंयोग, बार्जीलिंग।
- (36) श्री हरी किशोर सिंह नं० 2/15, श्रीकृष्णपाय, पटना।
- (37) प्रो० एम० एन० श्रीनिवास, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- (38) श्रीमती जमना देवी, झावरिया, मध्य प्रदेश।
- (39) श्री गणपत हीरालाल भगत, नागपुर।
- (40) श्रीमती अम्माना राजा, भूतपूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा), हैदराबाद।
- (41) सचिव (कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय।
- (42) अतिरिक्त सचिव (सा० वि०), खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय।
- (4) सदस्य सचिव (43) संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास विभाग, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय।

3. परिषद के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

- (1) सरकार को पंचायती राज से सम्बन्धित समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में सलाह देना ;
- (2) राज्यों में पंचायती राज के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना, जिसमें विशेष रूप से यह देखना है कि कौन-कौन सी जिम्मेदारियां इस प्रणाली के सुपुर्द की गई हैं और उन्हें निभाने तथा समस्या-क्षेत्रों का पता लगाने में यह कहाँ तक सक्षम है ;
- (3) सरकार को उन उपायों के बारे में सलाह देना जिनसे पंचायती राज के विकास तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक अनुकूल स्थानीय पहल सुनिश्चित की जा सके।

4. परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

5. परिषद की बैठक आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जाएगी, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी। परिषद् अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यकतानुसार समितियों का गठन कर सकती है।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

इन्द्र देव नारायण साही
अतिरिक्त सचिव

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और
नगर विकास मंत्रालय**

(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1969

संकल्प

विषय:—भारत सरकार के मुद्रणालयों में उत्पादन की लागत की जांच करने के लिए तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के मुद्रणालयों की लागत से तुलना करने के लिए लागत अध्ययन टीम (कास्ट स्टडी टीम) का गठन।

सं० एस०/एण्ड पी० 2/27(5)/53-पी.1—निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० एण्ड पी० 2/27(5)/53-पी.1 दिनांक 9 फरवरी, 1969, यथा संशोधित द्वारा गठित की गई लागत अध्ययन टीम की अवधि को भारत सरकार ने 30 अप्रैल, 1969 तक आगे बढ़ा दिया है।

2. टीम के विचारणीय विषय परिवर्तित बने रहे।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत सरकार के सभी मंत्रालय को भेज दिया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पं० प्रभाकर राव, संयुक्त सचिव

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1969

संकल्प

विषय:—हिन्दी में विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए हिन्दीभाषी राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन और उसकी समन्वय समिति की स्थापना।

सं० एफ० 6-41/69-आई०एल० II—1. शिक्षा आयोग (1964-65) ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। बाद में इस सिफारिश का अनुमोदन राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन (अप्रैल, 1967), संसद सदस्यों की शिक्षा समिति (जुलाई, 1967), और कुलपति सम्मेलन (सितम्बर, 1967) द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प (1968) में भी विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संकल्प के शब्दों में “प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग पहले से ही हो रहा है। अब उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाया जाना चाहिए”।

2. विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए यह अपेक्षित है कि माध्यम परिवर्तन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन भाषाओं में पुस्तकों का निर्माण किया जाए। इसके तथा इससे संबंधित कार्यों के लिए भारत सरकार

ने केन्द्र के अधीन चलने वाली एक योजना बनाई है जो 15 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कि जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत 1968-69 से शुरू होने वाली अवधि में प्रत्येक राज्य को अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इस वर्ष के लिए यह सहायता सामेदारी के आधार पर होगी अर्थात्, किए गए व्यय में 75 प्रतिशत भाग केन्द्र का और 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार का होगा। आगामी वर्षों में यह सहायता केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत आधार पर होगी। भारत सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् की इस सिफारिश पर किया है कि 1969-70 से केन्द्र के अधीन चलने वाली सभी योजनाएं 100 प्रतिशत आधार पर होगी।

3. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए राज्यों में चलने वाले कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा तैयार की और उसे परिपत्र के रूप में राज्य सरकारों को भेजा। इस रूपरेखा के द्वारा राज्य सरकारों से संगठन-व्यवस्था, प्रारम्भ की गई प्रायोजनाओं और उनकी योजनाओं को कार्यान्वित करने के उनके ढंग के संबंध में जानकारी मांगी गई है। पांच हिन्दी भाषी राज्यों के बारे में यह महसूस किया गया कि दुहरे काम से बचने के लिए उनके कार्यक्रमों में समन्वय रखने की आवश्यकता है। तदनुसार हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षा सचिवों और कुलपतियों तथा कुछ अन्य विशेषज्ञों का एक सम्मेलन 1 और 2 फरवरी, 1968 को वाराणसी में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी में मानविकी और विज्ञान विषयों में, जिनमें आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी और कृषि भी शामिल है, विश्वविद्यालय स्तर की अच्छी पुस्तकों के निर्माण का एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार करना था। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में इस क्षेत्र के विभिन्न कार्यकलापों में तालमेल बनाए रखने के लिए सम्मेलन की एक स्थायी समिति नियुक्त की जाए। बाद में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निश्चय यह किया गया कि समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु स्थायी समिति की सहायता के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग सचिवालय के रूप में काम करेगा।

4. हिन्दी भाषी राज्यों के कुलपतियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की पहली बैठक 24 और 25 मई 1968 को नई दिल्ली में और दूसरी बैठक 30 अक्टूबर, 1968 को पटना में हुई। स्थायी समिति ने 25 विषयनामिकाएं बनाई जिनमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे। विषय-नामिकाओं की बैठकें हुई और राज्य-मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके अनुसार 396 पुस्तकों का मौलिक लेखन और 1971 पुस्तकों का अनुवाद किया जाना है। उन्होंने विभिन्न विषयों की 812 उपलब्ध हिन्दी पुस्तकों का विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित करने के लिए अनुमोदन भी किया।

5. इस तरह स्थायी समिति ने हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण-कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की है। अब भारत सरकार का यह विचार है कि इस कार्य को ऐसे ढंग से करने के लिए, जिससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके, कुलपति सम्मेलन का अधिक व्यापक रूप में पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तदनुसार भारत सरकार ने, हिन्दी में विश्वविद्यालय

स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए एतद् द्वारा हिन्दी-भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन की स्थापना की है।

संघटन

- | | |
|---|------------|
| (1) केन्द्रीय शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्री | अध्यक्ष |
| (2) केन्द्रीय शिक्षा एवं युवक सेवा राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| (3) सभी हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षा मंत्री | सदस्य |
| (4) इन राज्यों के स्वायत्त मंडलों या पुस्तक निर्माण संबंधी ऐसी ही स्वायत्त अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष | सदस्य |
| (5) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | सदस्य |
| (6) हिन्दी-भाषी राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति | सदस्य |
| (7) कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | सदस्य |
| (8) कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय | सदस्य |
| (9) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग | सदस्य |
| (10) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय | सदस्य |
| (11) संयुक्त सचिव, प्रभारी-भाषा एवं पुस्तक-निर्माण, केन्द्रीय शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय | सदस्य-सचिव |

कार्यः— सम्मेलन के निम्नलिखित कार्य होंगे :

- (1) सभी हिन्दी भाषी राज्यों में पुस्तक-निर्माण की प्रगति का सामान्य पुनरीक्षण, और
- (2) सम्मेलन के सम्मुख प्रस्तुत सभी मामलों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को सलाह देना।

समन्वय समिति

6. उपर्युक्त सम्मेलन के अतिरिक्त, भारत सरकार एतद् द्वारा सम्मेलन की समन्वय समिति भी स्थापित करती है। इस समिति का संघटन इस प्रकार होगा :

- | | |
|---|-----------|
| (1) केन्द्रीय शिक्षा एवं युवक सेवा राज्य मंत्री | अध्यक्ष |
| (2) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग | उपाध्यक्ष |
| (3) सभी हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षा मंत्री या उनके प्रतिनिधि | सदस्य |
| (4) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (5) सभी हिन्दी भाषी राज्यों के स्वायत्त मंडलों या पुस्तक निर्माण संबंधी ऐसी ही अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि | सदस्य |
| (6) प्रत्येक हिन्दी भाषी राज्य से राज्य सरकार द्वारा नामित एक-एक प्रख्यात शिक्षा शास्त्री (कुलपति हो तो अधिक अच्छा है) | सदस्य |
| (7) कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (8) कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (9) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय | सदस्य |

- (10) संयुक्त सचिव, प्रभारी-भाषा एवं पुस्तक निर्माण, केन्द्रीय शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय

इस समिति के निम्न लिखित कार्य होंगे :

- (क) सभी हिन्दी-भाषी राज्यों के विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय,
- (ख) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देना जिससे दुहरा कार्य न हो सके, और
- (ग) सूचनाओं का आदान-प्रदान।

सम्मेलन की बैठक वर्ष में एक बार होगी। समन्वय समिति की बैठक हर तीसरे महीने हो सकती है किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होनी चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग सम्मेलन और समन्वय समिति की सहायता करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी हिन्दी भाषी राज्यों, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हिन्दी भाषी राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत-राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1969

सं० 22/1/69-सी०ए०-1(2)--इस मंत्रालय की 10 मार्च, 1969 की अधिसूचना सं० 22/1/69-सी०ए०-1(2) के क्रम में उदयपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री बी० एस० माथुर को भारत सरकार के संकल्प संख्या 6/25/63-ए०-10 (सी०-5), दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के पैराग्राफ 3-1-ए०-(6) के अनुसार, 3 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के बकाया भाग के लिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के एक साधारण सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए० एस० तलवार, अवर सचिव (सी०)

सिचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1969

सं० वि० का० बो-28(52)/67--आजादी मिलने के बाद देश में सिचाई के विकास में बड़ी प्रगति हुई है। आजादी मिलने के

समय जितने क्षेत्र में सिंचाई होती थी, अब उससे दुगुने क्षेत्र में सिंचाई होने लगी है। तथापि, देश में जितनी भूमि में काफ़त होती है, उसका लगभग 4/5 भाग अब भी पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहता है। देश के कई भागों में पिछले चार वर्षों में सूखा पड़ने के कारण और खाद्यान्न की तंगी रहने के कारण, अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का महत्व नितांत स्पष्ट हो गया है। इस संदर्भ में, अगली चार-पांच योजनावधियों में तलगत और भूमिगत, दोनों प्रकार के जल के अधिकतम समुपयोजन की और भी ज्यादा महत्व और ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघीय प्रदेशों के प्रशासनों से परामर्श करके देश में सिंचाई के भावी विकास के प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये एक सिंचाई आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है। इस आयोग का गठन इस प्रकार होगा :—

श्री अजित प्रसाद जैन, संसत्सदस्य अध्यक्ष
डा० एस० आर० सेन, अपर सचिव, उपाध्यक्ष
योजना आयोग

श्री ओ० पी० गुप्ता, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता, सदस्य
सिंचाई उत्तर प्रदेश

एक और सिंचाई अभियंता बाद में मनोनीत सदस्य
किया जाएगा

श्री डी० बी० रेड्डी, विस्तार आयुक्त, सदस्य
कृषि विभाग

श्री एन० एस० पारदासानी, सचिव, सदस्य
सिंचाई व बिजली विभाग, महाराष्ट्र बंबई
(अंशकालिक)

श्री के० एस० एस० मूर्ति, विशेष कार्य-अधिकारी, सचिव
सिंचाई व बिजली मंत्रालय।

2. इस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) भारत में 1903 से जब पिछले सिंचाई आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की थीं, लेकर अब तक सिंचाई के विकास का पुनर्वलोकन करना और भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये और वृष्टि की अनियमितताओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिये सिंचाई के अंशदान पर रिपोर्ट देना।

(2) उन क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की विस्तार-पूर्वक जांच करना, जो हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं और जहां खाद्यान्न की कमी रहती है, और यह सुझाना कि वहां पर कौन से अत्यावश्यक तथा न्यूनतम सिंचाई कार्यों को तुरंत ही हाथ में लिया जाए।

(3) अनाज में आत्मनिर्भरता लाने के लिये और अन्य फसलों की उपज को अधिकतम करने के लिये सभी किस्मों की सिंचाई के विकास की मोटी रूप-रेखा तैयार करना तथा इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित धन का मोटा अनुमान लगाना।

(4) बृहत् सिंचाई परियोजनाओं में पानी की सप्लाई की पर्याप्तता की जांच करना।

(5) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उनकी तैयारी की अवधि को कम करने के विशेष उद्देश्य से, सिंचाई कार्यों के आयोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन के लिये प्रशासनिक तथा संगठनात्मक प्रणाली की जांच करना।

(6) सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिये मान-दंड सुझाना।

(7) देश में सिंचाई के विकास से संबंधित अथवा किसी अन्य प्रसांगिक विषय पर विचार करना और उपयुक्त सुझाव देना।

3. इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. आयोग अपनी सिफारिशें यथाव्यवहार्य शीघ्र, परन्तु दो वर्षों के भीतर अवश्य ही, प्रस्तुत करेगा। यदि आयोग उचित समझे, तो वह किसी/किन्हीं विशिष्ट समस्या/समस्याओं पर अन्तरिम रिपोर्ट/रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकता है।

5. आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं बनाएगा। जिस प्रकार आवश्यक समझे, वह उसी प्रकार जानकारी मंगा सकता है और साक्ष्य ले सकता है। आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जो भी जानकारी और कागजात और सहायता चाहेगा, वे उसे देंगे।

6. भारत सरकार को यह विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघीय प्रदेश के प्रशासन इस आयोग को अपना पूरा सहयोग देंगे और उसकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघीय प्रदेशों के प्रशासनों को भेज दी जाए।

के० पी० मध्वरानी, सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 अप्रैल 1969

संकल्प (संशोधन)

सं० 7/1/69-उफ० आई० (एन० ए०)---फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कारों के सम्बन्ध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या-7/1/69-एफ० आई०- (एन० ए०) तारीख 7 फरवरी 1969 में निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं:—

(क) निम्नलिखित को नियम 3(1) के खण्ड (ज) के बाद जोड़ दिया जाए—

(ट) वर्ष के सर्वोत्तम गीतकार का पुरस्कार

राष्ट्रीय एकता के विषय पर सर्वोत्तम फिल्मी गीत लिखने वाले गीतकार को एक प्रशस्ति चिह्न।

(ख) नियम 3(1) के खण्ड (ट) को अब (ठ) बना दिया जाये।

- (ग) नियम 3 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की पंक्ति 3 और 7 में "स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक" शब्दों के बाद "गीतकार" शब्द जोड़ दिया जाय।
- (घ) नियम 10 के अन्तर्गत "सर्वोत्तम पार्श्वगायिका" शब्दों के बाद कौमा और "गीतकार" शब्द जोड़ दिया जाय।
- (ङ) नियम 13 के अन्तर्गत "सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक" शब्दों के बाद कौमा और "गीतकार" शब्द जोड़ दिये जायें।
- (च) नियम 25 के अन्तर्गत "संगीत निर्देशक" के बाद का कौमा हटा दिया जाय और "और गीतकार" शब्द जोड़ दिये जाएं।
- (छ) फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कारों के नियमों के परिशिष्ट में क्रम संख्या 13) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए:
- "14) गीतकार का नाम और पूरा पता" और वर्तमान संख्या 14), 15), और 16) को क्रमशः 15), 16), और 17) बना दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व-साधारण के सूचानार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 7 अप्रैल 1969

(फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार)

सं० 7/12/69-एफ० आई० (एन० ए०)—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता के विषय पर वर्ष के सर्वोत्तम फिल्मी गीत के गीतकार को भी एक पुरस्कार दिया जाएगा। 1968 में बनी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये प्रविष्टियों की अन्तिम तारीख 15 अप्रैल 1969 तक बढ़ा दी है ताकि इस पुरस्कार के सम्बन्ध में और प्रविष्टियां भेजी जा सकें।

हरि बाबू कंसल, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th April 1969

No. 19-Pres./69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

Name of the officer and rank

Shri Ram Nath Singh,
Constable 4896, 'F' Company,
5th Battalion,
Central Reserve Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Ram Nath Singh was posted in the 'F' Company of 5th Battalion of Central Reserve Police at Chhingchhip in Mizo Hills. On the 11th November, 1967, information was received that a party of hostiles was moving from village Raldan with the intention of attacking the Central Reserve Police Post. An ambush was laid on both sides of the track coming to Chhingchhip from Raldan. Shri Ram Nath Singh was deputed as L.M.G. gunner in the ambush party and was assigned the task of opening fire and engaging the hostiles. At about 1720 hours approximately 20 armed hostiles came near the place of ambush in two groups. On a signal from the ambush Commander, Shri Ram Nath Singh opened fire on the hostiles, who returned the fire and attempted to assault on the L.M.G. position. One of the hostiles rushed towards Shri Ram Nath Singh. Shri Ram Nath Singh remained undeterred and continued firing on the hostiles in utter disregard of his personal safety. It was because of the gallantry and presence of mind shown by Shri Ram Nath Singh that 4 hostiles were killed and some arms and ammunition were captured.

Shri Ram Nath Singh showed conspicuous gallantry and courage in this ambush operation.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th November, 1967.

New Delhi, the 10th April 1969

No. 20-Pres./69.—The following amendments approved by the President to the Table of Precedence published in Notification No. 11-Pres./68, dated the 28th February, 1968, as amended up to date, are published for general information :—

(a) In Article 8—

Add "Deputy Chairman, Planning Commission".

(b) In Article 16—

Delete the words "Deputy Chairman and" occurring before the words "Members of the Planning Commission".

(c) In Article 22—

Delete the words "Metropolitan Council" appearing after the words "Chief Executive Councillor".

(d) In Article 25—

Delete the words "Metropolitan Council" appearing after the words "Executive Councillors".

(e) In Article 29—

Delete the words "Metropolitan Council" appearing after the words "Chief Executive Councillor".

(f) In Article 30—

Delete the words "Metropolitan Council" appearing after the words "Executive Councillors".

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 31st March 1969

RESOLUTION

No. F.1-16/69-SW.3.—Whereas the Government of India under the Ministry of Education Resolution No. F.2-6/53-D2, dated the 12th August, 1953, had set up the Central Social Welfare Board at New Delhi, with the object of assisting the Voluntary Social Welfare Organisations throughout the country to maintain and develop their existing programmes and to dovetail them into the general pattern and have, from time to time, extended its term and reconstituted the Board, the last such occasion being with effect from the 16th February, 1968, vide the Department of Social Welfare Resolution No. F.1-100/65-SW.3 (Vol. II), dated the 15th February, 1968; and

Whereas the Government of India have, after careful consideration decided to register it as a Company under the name of "The Central Social Welfare Board" under Section 25 of the Companies Act, 1956 with effect from the 1st April, 1969;

Now, therefore, the Government of India hereby order that the said Central Social Welfare Board, established under their Resolution dated the 12th August, 1953, referred to above be dissolved with effect from the afternoon of the 31st March, 1969.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :

1. All the State Governments/Union Territories.
2. All Members of the Board.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. Planning Commission.
5. President's Secretariat.

6. Cabinet Secretariat.
7. Prime Minister's Secretariat.
8. Department of Parliamentary Affairs.
9. Central Social Welfare Board.
10. Press Information Bureau.
11. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.

ORDERED also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. RAMDAS, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 5th April 1969

No. 61/3/68-Poll. I(B).—The following statement showing the number of persons in detention under the preventive Detention Act, 1950 (4 of 1950) in various States as on the 31st December, 1968 is published for general information :—

Name of the State	Number of Persons in detention under the Preventive detention Act, 1950 on the 31st December, 1968.					
	Detained under section 3(1)(a) Clause				Detained under section 3(1)(b)	Grand Total
	(i)	(ii)	(iii)	Total of columns 2 to 4		
1	2	3	4	5	6	7
1. Andhra Pradesh	—	—	—	—	—	—
2. Assam	—	1,509	—	1,509	—	1,509
3. Bihar	—	5	—	5	—	5
4. Gujarat	—	—	—	—	—	—
5. Kerala	—	—	1	1	—	1
6. Madhya Pradesh	—	3	—	3	—	3
7. Tamil Nadu	—	—	—	—	—	—
8. Maharashtra	—	15	—	15	—	15
9. Mysore	—	1	—	1	—	1
10. Nagaland	—	—	—	—	—	—
11. Orissa	—	—	—	—	—	—
12. Punjab	*1	—	—	1	22	23
13. Haryana	—	—	—	—	—	—
14. Rajasthan	5	—	—	5	4	9
15. Uttar Pradesh	—	6	—	6	—	6
16. West Bengal	—	523	118	641	—	641
17. Delhi	3	—	—	3	3	6
18. Himachal Pradesh	—	—	—	—	—	—
19. Goa, Daman & Diu	—	—	—	—	—	—
20. Manipur	—	—	—	—	—	—
21. Tripura	—	%22	—	22	—	22
22. L. M. & A. Islands	—	—	—	—	—	—
23. Andaman and Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—
24. Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—
25. Pondicherry	—	—	—	—	—	—
26. Nafa	—	—	—	—	—	—
27. Chandigarh	—	—	—	—	—	—
TOTAL	9	2,084	119	2,212	29	2,241

*This Person was also detained under section 3(1)(a)(ii).

%These persons were also detained under section 3(1)(a)(iii).

G. K. ARORA, Dy. Secy.

RULES

New Delhi, the 19th April 1969

No. 15/1/69-AIS(I).—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in October, 1969 for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the following Services are, with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information.

- (i) The Indian Administrative Service,
- (ii) The Indian Foreign Service,
- (iii) The Indian Police Service,
- (iv) The Central Information Service, (Grade II) Class-I
- (v) The Indian Audit & Accounts Service,
- (vi) The Indian Customs & Central Excise Service,
- (vii) The Indian Defence Accounts Service,
- (viii) The Indian Income-tax Service (Class I),
- (ix) The Indian Ordnance Factories Service, Class I, (Assistant Managers Non-Technical),
- (x) The Indian Postal Service,
- (xi) The Indian Railway Accounts Service,
- (xii) The Military Lands and Cantonments Service, Class I,
- (xiii) The Indian Railway Traffic Service,
- (xiv) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands, Police Service, Class II,
- (xv) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,
- (xvi) The Customs Appraisers' Service, Class II,
- (xvii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II,
- (xviii) The Indian Foreign Service, Branch (B) Section Officers' Grade, Class II,
- (xix) The Railway Board Secretariat Service, Class II,
- (xx) The Armed Forces Headquarters Civil Service-Superintendent's Grade, Class II,
- (xxi) The Military Lands and Cantonments Service, Class II,
- (xxii) The Manipur Police Service, Class II,
- (xxiii) The Tripura Police Service, Class II,
- (xxiv) The Manipur Civil Service, Class II,
- (xxv) The Tripura Civil Service, Class II,
- (xxvi) The Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II, and
- (xxvii) The Pondicherry Civil Service, Class II.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services mentioned above. He may specify in his application as many of these Services as he may wish to compete for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service not specified by them.

N.B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the *order of preferences* for the services for which they wish to compete. They are advised to indicate as many Services as they wish to, so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st December, 1969.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled

Tribes Order, 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, all Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and who have been released during 1969 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1970 will be eligible to appear at this examination.

Provided that Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, who were released prior to 1969 shall be eligible to appear at the examination to the extent and in accordance with the provisions of Rule 8.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, "release" means

- (i) actual release according to a phased programme in the case of Emergency Commissioned Officers,
- (ii) actual release at the end of the tenure of their service in the case of Short Service Commissioned Officers,
- (iii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service,

from the Armed Forces after a spell of service, and *not* during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 3.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 4.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other Services, a candidate must be either—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Sikkim, or
- (c) a subject of Nepal, or
- (d) a subject of Bhutan, or
- (e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories:—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.
- (iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must *not* have attained the age of 24 years on the 1st August of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 9(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of

- (i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);
 - (ii) 23 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);
 - (iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the second year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);
 - (iv) 21 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);
 - (v) 20 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training); and
 - (vi) 19 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training).
- (b) The age limit prescribed above will be relaxable:—
- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
 - (ii) up to maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;
 - (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
 - (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
 - (v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
 - (vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
 - (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Damian and Diu;
 - (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
 - (ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
 - (x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
 - (xi) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
 - (xii) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
 - (xiii) up to a maximum of three years, if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;
 - (xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;
 - (xv) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965 and
 - (xvi) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965.

NOTE 1.—The provisions contained in clauses (xiii) and (xiv) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a).

NOTE 2.—The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1966.

Provided that a candidate who had not attained the age specified in Rule 6 above on the 1st August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training), but had attained that age of on the 1st August of the year succeeding the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) shall be permitted to compete only once at the examination.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

8. Subject to the provisions of these Rules,

- (1) a candidate who is eligible to take only one chance must take the examination held in the year preceding the year of his release; and
- (2) a candidate who is eligible to take two chances must take the examinations held in the year preceding the year of his release and the year of his release.

Provided that

(a) a candidate who has been invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service may, subject to the exceptions mentioned in the Notes below this rule, take the examination to be held in 1969.

- (i) as his only chance, if invalided during 1968 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1968 examination, or during 1969 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1969 examination, and if eligible to take one chance;
 - (ii) as his first chance, if invalided during 1968 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1968 examination, or during 1969 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1969 examination, and if eligible to take two chances;
 - (iii) as his second chance, if invalided during 1967 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1967 examination, or during 1968 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1968 examination, and if eligible to take two chances;
 - (iv) as his second chance, if invalided during 1968 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1968 examination, and if he was due for release during 1969 according to a phased programme (in the case of an Emergency Commissioned Officer) or at the end of the tenure of his service (in the case of a Short Service Commissioned officer);
- (b) a candidate who had been admitted by the Commission to the examination held in 1967, but who could not appear thereat owing to exigencies of service in the Armed Forces, may take the examination to be held in 1969, as his second chance, if eligible to take two chances.
- (c) A candidate released during 1968 or earlier appearing at the examination under Rule 9(b), may take the examination to be held in 1969, as his second chance, if eligible to take two chances.

NOTE 1.—The provisions contained in proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1967, 1968 and 1969 who were due for release in 1967, 1968 and 1969 respectively according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the tenure

of their service (in the case of Short Service Commissioned Officers).

NOTE 2.—The provisions contained in clauses (i) and (ii) of proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1968 who were due for release in 1969 according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the tenure of their service (in the case of Short Service Commissioned Officers).

NOTE 3.—The provision contained in clause (iii) of proviso (a) to this rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1967 who were due for release in 1968 according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the tenure of their Service (in the case of Short Service Commissioned Officers).

9. (a) A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that—

- (i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.
- (ii) a candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.
- (b) A candidate who, when he appeared before a Service Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a recognised institution *e.g.*, a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, had not acquired such qualification, will also be eligible to appear at the examination.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination *vide* Sub-Rule (a) of this Rule, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

10. A candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will not be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in column (iii) below.

Sl. No.	Service to which appointed	Services for which eligible to compete
1.	Indian Police Service	I.A.S., I.F.S. and other Central Services, Class I.
2.	Central Services, Class I other than I.F.S.	I.A.S., I.F.S. and I.P.S.
3.	Central Services, Class II Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Manipur Civil Service, Tripura Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service, Pondicherry Civil Service, Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service.	I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services Class I.

11. A candidate serving in the armed forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. A candidate who is himself the officer Commanding his Unit must submit his application through his next superior officer.

All other candidates in Government Service must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period;

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service.

18. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned officers Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf from time to time.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s).

19. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

20. Due consideration will be given to the preferences for various Services expressed by a candidate at the time of his application.

Provided that a candidate who is appointed to the I.A.S. of I.F.S. on the results of an earlier examination will not be considered for allotment to any other Service on the results of this examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that Service in column (iii) below, on the results of this examination.

Sl. No.	Service to which appointed	Service to which allotment will be considered
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service	I.A.S., I.F.S., and other Central Services, Class I.
2.	Central Services, Class I .	I.A.S., I.F.S., and I.P.S. other than L.F.S.
3.	Central Services, Class II Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Manipur Civil Service, Tripura Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service Pondicherry Civil Service, Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service.	I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services Class I.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of each Service.

23. No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

24. Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service will be allowed to marry persons other than of Indian nationality.

25. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

26. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

A. N. BATASYAL, Under Secy.

APPENDIX I

*List of Universities approved by the Government of India
(vide Rule 9)*

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.
The Mandalay University.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).
The National University of Dublin.
The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.
The Dacca University.
The University of Sind.
The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of Qualifications recognised for admission to the examination (vide Rule 9).

1. French Examination "Propedeutique."
2. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
3. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
4. Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.
5. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Tech. Education.
6. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."
7. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
8. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX II

Plan of the Examination

1. The competitive examination comprises :
 - (a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 450 marks.
 - (b) *Viva voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 250 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) Essay	3 hours	150
(ii) General English	3 hours	150
(iii) General Knowledge	3 hours	150

3. The syllabus for the examination will be as in the attached Schedule.

4(a). The question papers in 'Essay' and 'General Knowledge' vide items (i) and (ii) respectively in para 2 above may be answered in English or in any one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, *viz.*, Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Candidates exercising the option to answer both the papers in a language other than English must choose the same language for both the papers. The option will apply to a complete paper and not to a part thereof.

(b) The question paper in 'General English' vide item (ii) in para 2 above must be answered in English.

Note. I. A candidate desirous of answering the question paper (s) mentioned in para 4(a) above in a language other than English must already indicate, in column 33 of the Application form the name of that language against the paper(s) concerned. If no entry is made in the said column in respect of either or both of the papers, it will be assumed that the paper/papers will be answered in English. *The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration or addition in the said column shall be entertained.*

NOTE II.—Candidates exercising the option to answer the paper (s) referred to in para 4(a) above in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution will be required to write their answers in the respective script indicated below:

Language	Script
1. Assamese	Assamese
2. Bengali	Bengali
3. Gujarati	Gujarati
4. Hindi	Devanagiri
5. Kannada	Kannada
6. Kashmiri	Persian
7. Malayalam	Malayalam
8. Marathi	Devanagiri
9. Oriya	Oriya
10. Punjabi	Gurmukhi
11. Sanskrit	Devanagiri
12. Sindhi	Devanagiri or Arabic
13. Tamil	Tamil
14. Telugu	Telugu
15. Urdu	Persian

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. If a candidate handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

(vide para 3 of Appendix II)

PART A

1. *Essay.*—Candidates will be required to write an essay. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subjects of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English.*—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge.*—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART B

Viva Voce : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The candidate will be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces. The object of the *Viva Voce* is an assessment of the suitability of the candidate for the Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers.

The technique of the *Viva Voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the mental qualities of the candidate e.g., mental alertness and initiative, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

APPENDIX III

The Appendix briefly describes the conditions of service as applicable to candidates recruited through the regular I.A.S. etc. Examination. The seniority and pay of the candidates who may be appointed on the results of this examination would be regulated in accordance with the special orders issued by the Government in this behalf.

1. *Indian Administrative Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000 (18 years).

Senior Scale—

(i) Time Scale.—Rs. 900 (6th year or under) 50—1,000—60—1,600—50—1,800 (22 years).

(ii) Selection Grade.—Rs. 1,800—100—2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,500, to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will start on the Junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(i) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty-one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Mission whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is, confirmed in his appointment. If, however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.

Second Year—Rs. 400 per mensem.

Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examinations.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

- (i) Free furnished accommodation according to status.
- (ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.
- (iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.
- (iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.
- (v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.
- (vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted to various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.
- (vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (PLCA) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund*.—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits*.—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government Servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service*.—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b) } As in clauses (b), (c) and (d) for the Indian
(c) } Administrative Service.
(d) }

(e) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (18 years).

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300 (22 years).

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,600—100—1,800.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay.—Rs. 1,800—100—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Director, Intelligence Bureau.—Rs. 3,000.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

(g) }
(h) } As in clauses (g), (h), (i) and (j) for the Indian
(i) } Administrative Service.
(j) }

4. The Central Information Service, Grade II (Class I)

(a) The Central Information Service consists of posts all over India in various media organisations of the Ministry of Information and Broadcasting requiring journalistic and similar professional qualifications with previous experience of work on a newspaper or news agency or publicity organisations. The service was constituted with effect from 1st March, 1960.

(b) The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Class I	
Selection Grade . . .	Rs. 2,500/- (fixed).
Senior Administrative Grade	
(Senior Scale) . . .	Rs. 1,800—100—2,000.
(Junior Scale) . . .	Rs. 1,600—100—1,800.
Junior Administrative Grade	
(Senior Scale) . . .	Rs. 1,300—60—1,600
(Junior Scale) . . .	Rs. 1,100—50—1,400.
Grade I . . .	Rs. 7,000—40—1,100—50/2—1,250..
Grade II . . .	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.
Class II (Gazetted)	
Grade III . . .	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
Class II (Non-Gazetted)	
Grade IV . . .	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485.

(c) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies, as specified below, in the following grades of the service :—

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12½ %
Grade I	25 %
Grade II	50 %
	of permanent posts.
Grade IV	100 %

Vacancies in Grade III are filled by selection in equal proportion on the basis of—

- (i) the recommendation of a Departmental Promotion Committee, and
- (ii) a departmental competitive examination from amongst officers who have completed five years service in a duty post in Grade IV or in any higher grade.

50% permanent and all temporary vacancies in Grade II, 75% vacancies in Grade I and 87½% vacancies in the Junior Administrative Grade (Junior Scale) are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

Vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade (Senior Scale), and Senior Administrative Grade (Junior Scale), and Junior Administrative Grade (Senior Scale) are filled by selection from amongst officers holding duty posts in the respective next lower grade, in case no suitable officer is available for such promotion, recruitment to such vacancies in the Selection Grade and Senior Administrative Grade is to be made in consultation with the Union Public Service Commission. Vacancies in the Junior Administrative Grade, (Senior Scale) are filled by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from amongst officers holding duty posts in the Junior Scale of that Grade.

The Government can fill, in consultation with the Union Public Service Commission, in any grade a number of posts not exceeding 10% of the strength of that grade, by the appointment of officers of State Publicity Organisations on deputation, for such period not exceeding five years, as the Government may specify. The posts so filled are taken into account in determining the number of posts to be filled by promotion or by direct recruitment.

(d) (i) Direct recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communication, on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the National Academy of Administration. The total period of training will be about 15 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration and first and second departmental tests at the Indian Institute of Mass Communication, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or reversion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become an efficient, Grade II officer of the Service, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. On passing the first departmental test, the pay of Probationers will be raised to Rs. 450/- in the scale of pay of Grade II of the Central Information Service. On passing the second departmental test, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480/-. The pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to other conditions as may be found necessary. In case any of the Probationer does not pass the 'end-of-the-course-test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

(iv) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

NOTE.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

5. Indian Audit and Accounts Service.

6. Indian Customs and Central Excise Service.

7. Indian Defence Accounts Service.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the department examinations within period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms, the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of pay :—

Indian Audit and Accounts Service :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the End-of-the-Course Test at the National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which, under the Department regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

NOTE 4.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will however be regulated subject to the provisions of F.R. 22(B)(1).

Indian Customs and Central Excise Service :

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise, Class I, Assistant Collector of Central Excise, Assistant Collector of Customs. Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Deputy Collector of Customs, Deputy Collector of Central Excise, Additional Collector, Appellate Collector. Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.

Collector of Customs, Collector of Central Excise. Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 2 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of the Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation Government may confirm the officer in his/her appointment or if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him/her from the Service or may extend his/her period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) The Indian Customs and Central Excise Service, Class I, carries with it a definite liability for service in any part of India.

NOTE 1.—A probationary officer will start on the minimum of the time scale of pay of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—An officer on probation will not be allowed pay in the time scale above the stage of Rs. 400/- unless he/she passes the prescribed departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer in the Indian Customs and Central Excise Service, Cl. I will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

NOTE 4.—During the period of probation, an officer will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the National Academy of Administration, Mussoorie, for a Foundational Course training. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. He/she will have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the-course' test and one of the parts of the Departmental Examination he/she will be granted a first advance increment raising his/her pay to Rs. 450/-. On passing both the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted the second advance increment raising his/her pay to Rs. 480/-. His/her pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless he/she has completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, a probationer does not pass the 'end-of-the-course' test at the Academy, his/her first advance increments will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second advance increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 5.—It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs & Central Excise Service, Class I, which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining. The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will, however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; 'provided further that in the case of an officer who does not pass the end-of-the-course test at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would

have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination whichever is earlier.

8. *Indian Income-tax Service, Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become an efficient Income Tax officer, the Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Income-tax Officer, Class I.—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income-tax.—

Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.

Commissioners of Income-tax.—

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the National Academy of Administration, Mussoorie and the Income-tax Training College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test : In addition, I & II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the I departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, he/she does not pass the end-of-the-course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the Constitution of the Income Tax Service, Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

9. *The Indian Ordnance Factories Service, Class I (Non-Technical Cadre).*—Appointments will be made to the posts of Assistant Manager (Non-Technical). The candidate will be on probation for a period of two years during which period he will undergo such practical training and pass such departmental and language tests as Government may prescribe.

On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

The selected candidate will be required to execute a bond at the time of his appointment that he will continue to serve in the Indian Ordnance Factories Service for a minimum period of three years after successful completion of his period of probation.

Assistant Managers, for whom the revised scale of pay is Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950, are eligible for promotion, on the basis of merit, to higher grades in the I.O.F.S., as shown below :—

Post	Scale of Pay
1. Deputy Manager (Non-Technical) Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.
2. Manager (Non-Technical)/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,100—50—1,400.
3. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade II).	Rs. 1,300—60—1,600.
4. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade I).	Rs. 1,600—100—1,800.
5. Deputy Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,800—100—2,000.

10. *Indian Postal Service.*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay.—

Time Scale :—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmasters-General : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,500—125/2—2,750.

Senior Member, Posts and Telegraphs Board : Rs. 3,000.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie they will have to pass the 'end-of-the-course test'. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end-of-the-course test' and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which, under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

Provided that the pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(h) Selected candidates will be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government.

11. *Indian Railway Accounts Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo a course of training at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the test prescribed by the College authorities. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the test at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund; as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the leave rules for the time being in force as applicable to officers of Indian Railways.

The leave rules are, however, liable to revision in the light of the Pay Commission's recommendations. They will not be permitted to retain the present leave rules, if so decided by the Government.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows, that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(i) Scales of pay :—

(a) Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

(b) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

12. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II).* (a) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training in Cantonment and Land Administration as may be prescribed by Government for a period of not less than six months.

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para, (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month,

terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scale of pay are as under :—

Administrative Posts

(f) Director, Military Lands and Cantonments. Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(ff) Joint Director, Military Lands and Cantonments. Rs. 1,600—100—1,800.

(fff) Deputy Director, Military Lands and Cantonments. Rs. 1,300—60—1,600.

(iv) Assistant Director, Military Lands and Cantonments. Rs. 1,100—50—1,400.

Class I

(v) Deputy Assistant Directors, Military Lands and Cantonments, Military Estates Officers, and Executive Officers. Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Class II

(vi) Executive Officers. Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.

(vif) Assistant Military Estates Officers. Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable. (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) All promotion will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

13. *Indian Railway Traffic Service*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para. (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

- (b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of this training and any other moneys paid to him during the period of his probation.
- (c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post, provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should as a rule, be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examination may result in the termination of the service and will, in any case, involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post the Probationary Officers will be required to pass a final examination both practical and theoretical, and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

- (d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

- (e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules :—

- (a) will be governed by the Railway Pension Rules; and
- (b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund;

as amended from time to time.

- (f) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.
- (g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

The Leave Rules are liable to revision in the light of the accepted recommendations of the Pay Commission. They will not be permitted to retain the present Leave Rules, if so decided by the Government.

- (h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.
- (i) The relative seniority of officers appointed will ordinarily be determined by their order of merit in the competitive examination; if the period of training and consequently the period of probation has to be extended in any particular case due to the training having not been completed satisfactorily, the officer will be liable to lose seniority. The Government of India, however, reserve the right of fixing seniority at their discretion in individual cases. They also

reserve the right of assigning to officers appointed otherwise than by a competitive examination positions in the seniority list at their discretion.

(j) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2 1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 13,00—60—1,600. (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade : Rs. 1600—100—1,800. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental test and being subsequently confirmed, their pay will from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In as such cases the date of future increments will not be affected.

Advanced increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the Officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of Service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

- (k) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

- (l) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

- (m) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case, the officers will not be confirmed till they pass the test, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

NOTE 4.—During the period of training, the probationer has to work as a Guard, Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Train Examiner, Assistant Loco Foreman, Assistant Controller, etc. as detailed below. After completion of training when the probationer is posted against a working post, his duties involve travelling with no facilities for camping at way-side stations. He has to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control Offices and stations. The work is arduous and will involve night duties.

(1) Length of Course—Two years.

Item	Period
1. National Academy of Administration, Mussoorie	4 Months
2. Baroda Staff College (First Phase)	3 months
3. Area School to learn Guard's duties	1 month
4. Working as Guard	$\frac{1}{2}$ month
5. Booking/Parcel Office, Goods Shed and Transshipment Shed	1 month
6. Traffic Accounts and Travelling Inspector of Accounts	1 $\frac{1}{2}$ months
7. Area School to qualify as Assistant Station Master	1 month
8. Working as Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	3 months
9. Working as Assistant Loco-Foreman	$\frac{1}{2}$ month
10. Working as Assistant Controller	2 months
11. (a) Training in Divisional Office	1 month
(b) Training as Power Controller	$\frac{1}{2}$ month
12. Baroda Staff College (Second Phase)	1 $\frac{1}{2}$ months
13. Eastern Railway Headquarters Office (Operating)	1 $\frac{1}{2}$ months
14. Eastern Railway Headquarters Office (Commercial)	1 $\frac{1}{2}$ months
	23 $\frac{1}{2}$ months
Period set apart for journey time for taking up various items for training and in case capable leave	$\frac{1}{2}$ month
	24 months

NOTE :—Items 3 to 11 which will cover 1 year will be in Asansol Division.

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

14. Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II.—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1,000/- fixed.

Grade II—Time scale—Rs. 350—25—500—30—530—EB—30—800.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders. They are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

15. The Central Secretariat Service, Section Officer's Grade, Class II—

(a) The Central Secretariat Service has, at present, the following grades :—

Grade	Scale of pay
Selection Grade—Deputy Secretary or equivalent	Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.
Grade I—Under Secretary	Rs. 900—50—1250.
Section Officer's Grade	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Assistant's Grade	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Selection Grade and Grade I are controlled by the Ministry of Home Affairs on an all-Secretariat basis. Section Officers'/Assistant's Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruit to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. Customs Appraisers' Service, Class II.

(a) Recruitment is made in the grade of appraiser in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. Appointments are made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. During the period of probation the candidates will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Board of Excise & Customs may prescribe. They will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 375/- unless they pass the prescribed departmental Examination in full.

(b) If on the expiration of the period of probation or any extension thereof the appointing authority is of the opinion that the selected candidate is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension thereof he is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation he may discharge him from the service or pass such orders as he thinks fit.

(c) On the successful completion of the period of probation and after passing of the departmental examination the officers will be considered for confirmation in the grade.

(d) The candidates will be eligible for promotion to the next higher grade of Principal Appraiser (Rs. 600—35—950) after they have completed five years' service as Appraisers. Thereafter they will be eligible for promotion to the next higher grade of Assistant Collector (Rs. 400—1,250).

(e) Regarding leave, pension the officers will be treated like other Class II officers in Central Government department. As regards other terms and conditions of their service, they will be governed by the provisions in the Recruitment Rules for the Customs Appraisers' Service, Class II. These rules particularly provide that the members of the service will be liable to posting in any equivalent or higher posts under the Central Board of Excise and Customs anywhere in India.

17. Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period for probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories.

(e) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 900—50—1,250.

Grade II—Time scale—Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion Regulations, 1955).

(f) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scale of pay.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at place either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Services Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

18. Indian Foreign Service, Branch 'B', Section Officers' Grade, Class II—

(a) 25% of the maintenance vacancies in the Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Class II) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent posts or if his work and conduct have, in the opinion of Government, been unsatisfactory, may either discharge him from the service, or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The total period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clause.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Commerce and Industry they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While Serving in Indian Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS(B) in the scale of Rs. 900—50—1,250, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of the Grade I of the General Cadre of the IFS(B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of IFS(A) in the scale of pay of Rs. 900 (6th years or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service, Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce and Industry. They are, however liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During Service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS(PLCA) Rules, 1961, as made applicable to I.F.S.(B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

- (ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.
- (iii) Return air passages to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.
- (iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.
- (v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.
- (vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.
- (vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.
- (j) The revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.
- (k) While in India, officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.
- (l) Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.
- (m) Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

19. The Railway Board's Secretariat Service, Class II—

(a) The Railway Board Secretariat Service consists of the following :—

Service	Scale of Pay
(i) Assistant Director/Under Secretary	Rs. 900—50—1,250.
(ii) Section Officer	Rs. 350—25—500—30—590—EB 30—800—EB—30—830—35—900
(iii) Assistant	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from Service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be in charge of branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligible for appointment to higher posts in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admissible to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that funds as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and Class II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Government employees headquartered at New Delhi.

20 The Armed Forces Headquarters Civil Service, Superintendents' Grade, Class II—

(a) The Armed Forces Headquarters Civil Service, has at present, the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Senior Civilian Staff Officer	Rs. 1100—50—1400.
Civilian Staff Officer	Rs. 740—30—800—50—1150.
Superintendents' Grade	Rs. 350—25—500—30—590—EB 30—800.
Assistants' Grade	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

The above Service caters for the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations of the Ministry of Defence.

Direct recruitment is made to the Superintendents Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Superintendents' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) In the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations of the Ministry of Defence, Superintendents will normally be heads of 'Sections' while Civilian Staff Officers will normally be in charge of one or more Sections.

(f) Superintendents will be eligible for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be eligible for appointment to the Grade of Senior Civilian Staff Officer of the Service and to other administrative post in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time, in respect of civilians paid from the Defence Service Estimates.

21. Manipur Police Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Manipur may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Manipur.

(e) Scale of pay—Rs. 300—25—450—EB—30—600—EB—30—900.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Manipur Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

22. Tripura Police Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Tripura may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Tripura.

(e) Scale of pay Rs. 300—30—510—EB—30—750—EB—30—900.

A person recruited on the results of competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Tripura Police Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

23. Manipur Civil Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Manipur may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Manipur.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1000—40—1200.

Grade II—Rs. 350—30—500—EB—30—650—EB—35—1000.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Manipur Civil Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

24. Tripura Civil Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Tripura may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Tripura.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1175/- fixed.

Grade II (Time-scale)—Rs. 325—30—475—35—545—EB—35—825—EB—35—1000.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Tripura Civil Service Rules 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

25. Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Territory of Goa, Daman and Diu may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade II—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800 EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Goa, Daman and Diu Civil Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

26. Pondicherry Civil Service, Class II

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Pondicherry may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry.

(e) Scale of pay—Rs. 375—25—800.

A person recruited on the results of competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry Civil Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India, reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

The classification of various Services under the two categories, namely "Technical" and "Non-technical" will be as under :—

A. Technical

(1) Indian Railway Traffic Service.

(2) Indian Police Service and other Central Police Services Class II.

B. Non-Technical

I.A.S., IFS, IA & AS, Indian Customs Service, Indian Railway Accounts Service, Railway Board Secretariat Service Class II, Indian Defence Accounts Service, Income Tax Officers (Class I), Indian Postal Service (Class I), Military Lands and Cantonments Service Class I & II and other Central Civil Services Class I & II.

1. To be passed as fit for appointment as candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
1. Indian Railway Traffic Service	152 cm 150 cm	84 cm 79 cm	5 cm (For men) 5 cm (For women)
2. Indian Police Service, Delhi / Himachal Pradesh & Andaman & Nicobar Islands Police Service Class II, Manipur Police Service Class II and Tripura Police Service, Class II.	165 cm 150 cm	84 cm 79 cm	5 cm (For men) 5 cm (For women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The Candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then

be recorded in centimetres, 84–89, 86–53.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of a half of a kilogram should not be noted.

6.(a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and vision with or without glasses for different types of Services.

Class of Service	Distant vision		Near vision	
	Better eye (Corrected)	Worse eye (vision)	Better eye (Corrected)	Worse eye (vision)
Class I & II				
(i) Technical	6/6	6/12 or 6/9	J.I.	J.II
(ii) Non-Technical	6/9	6/12	J.I	J.II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of Vision.* The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.* Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2), dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retino-graphy is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and require specialized set up, and equipment; and thus are not possible as a routine test in a medical check up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employees.

(g) *Colour Vision:* At the time of referring the candidates for medical examination, the Ministry/Department concerned will have to inform the Medical Board that the candidate is for a Technical Service (including Field Service) requiring colour vision examination or Non-Technical Services may not require colour vision and this should be decided by the Ministry/Department concerned and intimated to the Medical Board at the time of the medical examination.

(h) *Ocular conditions other than visual acuity:—*

(i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity, should be considered a disqualification.

(ii) *Squint:* For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One Eye:* The usual effect of one eye is that it does affect stereoscopic vision or perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may, therefore, recommend such one eyed persons if it is satisfied that he can perform all the functions for the particular job for which he is a candidate provided further that the visual acuity in the functioning eye is 6/6 for distant vision and 0.6 for near vision and the refractive error is not more than plus or minus 4.00 D.

(i) *Contact Lenses:* During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure.* The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15–25 years of age the average is about 100 plus age.

(ii) With subjects over 25 year of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B. As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be free from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readiness. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a

standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

- (a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services.
- (b) that his speech is without impediment;
- (c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);
- (d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;
- (e) that there is no evidence of any abdominal disease;
- (f) that he is not ruptured;
- (g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;
- (h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;
- (i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;
- (j) that there is no congenital malformation or defect;
- (k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;
- (l) that he bears marks of efficient vaccination; and
- (m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Ministry of Home Affairs on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters)
2. State your age and birth place
2. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No', and if the answer is 'Yes', state the name of the race
3. (a) Have you ever had small-pox, Inter-mittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of bloods, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis?
- Or
- (b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?
4. When were you last vaccinated?
5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause?

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers, living, their ages and state of health	No. of brothers, dead, their ages at, and cause of death
--	--	---	--

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at, and cause of death
--	--	---	--

7. Have you been examined by a Medical Board before ?
8. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for ?
9. Who was the examining authority ?
10. When and where was the Medical Board held ?
11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known
- I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1. General development: Good Fair Poor

Nutrition : Thin Average Obese

Height (Without shoes) Weight

Best Weight When ? any recent change in weight ? Temperature

Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin : Any obvious disease

3. Eyes :

(1) Any disease

(2) Night blindness

(3) Defect in colour vision

(4) Field of vision

(5) Visual acuity

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph. Cyl. Axis
Distant vision	R.E.		
	L.E.		
Near vision	R.E.		
	L.E.		
Hypermetropia	R.E.		
Manifest	L.E.		

4. Ears : Inspection Hearing : Right Ear Left Ear

5. Glands Thyroid

6. Condition of teeth

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ? Rate Standing

After hopping 25 times

2 minutes after hopping

(b) Blood Pressure : Systolic Diastolic

9. Abdomen : Girth Tenderness Hernia

(a) Palpable : Liver Spleen

Kidneys Tumours

(b) Hemorrhoids Fistula

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities.

11. Loco-Motor System : Any abnormality

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance

(b) Sp. Gr.

(c) Albumen

(d) Sugar

(e) Casts

(f) Cells

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

15. (i) State the Services for which the candidate has been examined :—

(a) IAS & IFS

(b) IPS, Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service

(c) Central Services. Class I & II

(ii) Has he been found qualified in all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in :—

(a) IAS & IFS

(b) IPS, Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police, Service (see especially height, chestgirth, eye sight, colour blindness and locomotive system)

(c) Indian Railway Traffic Service. (see especially height, chest, eye sight, colour blindness).

(d) Other Central Services Class I/II

(iii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit

(ii) Unfit on account of

(iii) Temporary unfit on account of

Place

Date

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY*New Delhi, the 7th April 1969***RESOLUTION***Iron Ore Export (Project) Committee*

No. 15/66/64-68/M&F.—In further modification of Government of India Resolution No. 15/49/64-M&F, dated 3-10-1963 as amended by Resolutions No. 15/66/64-M&F, dated 15-2-1965, 19-10-1965, 11-4-1967, 12-5-1967 and 28-9-1968, Government of India have decided that Para 3 of the Resolution regarding constitution of the above-mentioned Committee may be amended as follows :—

"3. Constitution

The Constitution of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Chairman, Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd.

Members

2. Chairman, National Minerals Development Corporation Ltd.
3. Adviser (Industry and Minerals)—Planning Commission.
4. Joint Secretary concerned with development of iron ore mines—Department of Mines and Metals.
5. Joint Secretary (Port and Transport)—Department of Shipping and Transport.
6. Joint Secretary concerned with H.E.C., M.A.M.C. and other Heavy Engineering Projects—Department of Industrial Development.
7. Joint Secretary concerned with iron ore exports—Department of Foreign Trade.
8. Director (Transport)—Railway Board.
9. Director (Planning)—Railway Board.
10. Director (Plan Finance)—Ministry of Finance (Department of Expenditure).

Member-Secretary

11. Director concerned with exports of iron ore—Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. C. ALEXANDER, Jt. Secy.

(Department of Foreign Trade)

New Delhi, the 8th April 1969

RESOLUTION

No. 14(9)Plant(A)/66.—In the Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) Resolution No. 14(9)Plant(A)/66, dated the 13th March, 1969 published in the Gazette of India, for the name "Shri W. H. G. Baird" occurring against S. No. (v) in para 2 thereof, the name "Shri J. C. Crawford" shall be substituted.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. L. GUPTA, Under Secy.

**MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
AND MINES AND METALS**

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 2nd April 1969

RESOLUTION

No. 25(1)/68-OR.—The Government of India are pleased to constitute an Experts' Committee consisting of the following persons to study and report upon the techno-economic

feasibility of locating another oil refinery at a suitable location in Assam :

- (1) Shri B. S. Negi, Member (Exploration) ONGC; (Convener).
- (2) Dr. Hari Narayan, Director, National Geophysical Research Institute.
- (3) Dr. M. G. Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum.
- (4) Dr. A. K. Ghosh, Economic Adviser, Railway Board.
- (5) Shri S. D. Bhambri, General Manager, IOC (Marketing Division).

(2) The Experts' Committee will study and report on the following :

- (i) Crude oil resources of Assam, yearly rate of production from the various fields and the quantities that will remain available after meeting fully the requirements of the existing refineries at Digboi, Gauhati and Barauni operating to their optimum design capacities.
- (ii) The nature and extent of demand for petroleum products within the State of Assam existing and in future, and the area of economic distribution for marketing the additional production.
- (iii) Techno-economic feasibility and comparative economics of establishing a new refinery or expansion of one or more of the existing plants, taking also into account the means of transport available or proposed.
- (iv) Other relevant factors which may have a bearing on the establishment of the additional refining capacity in Assam.

3. The Committee should also consider the views of the Government of Assam and others on this subject. The Committee should submit its report to the Government of India within a period of three months.

M. V. RAJWADE, Jt. Secy.

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT &
COMPANY AFFAIRS**

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi, the 21st March 1969

RESOLUTION

No. 28-17/68-HECHE.—Reference this Ministry's Resolution No. 28-2/66-HECHE, dated the 28th March, 1967 constituting a Committee to review the activities of and advise on the research and development programme of the Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal.

2. As Shri K. C. Lall has since relinquished charge as Chairman, Heavy Electricals (India) Limited, he has ceased to be a member of the said Committee.

3. Shri O. S. Murthy, Chairman, Bharat Heavy Electricals Ltd. is nominated as Member on the aforesaid Committee with immediate effect in place of Shri D. C. Bajjal who has since relinquished charge as Chairman Bharat Heavy Electricals Ltd. Alternate to Shri O. S. Murthy will be Shri H. C. Keskar, Chief, Planning and Development, Bharat Heavy Electricals Ltd. in place of Shri V. Krishnamurthy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Works, Housing & Urban Development)

New Delhi, the 5th April 1969

RESOLUTION

SUBJECT :—*Constitution of a Cost Study Team to study the cost of production in Government of India Presses vis-a-vis private presses.*

No. S&PII/27(5)/53-PI.—The Government of India is pleased to further extend till the 30th April, 1969 the term of the Cost Study Team set up *vide* Ministry of Works, Housing and Supply Resolution No. S&PII/27(5)/53-PI, dated the 9th February, 1968 as amended.

2. The terms of reference of the Team remain unchanged.

ORDER

1. ORDERED that the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. PRABHAKAR RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 2nd April 1969

RESOLUTIONS

No. 6-45/67-Genl.II.—The Government of India have decided that the Central Advisory Committee for Agricultural Production set up under their Resolution of even number dated the 22nd December, 1967 will *inter-alia* consist of four representatives of Agricultural Administrators, Agricultural Economists and Agricultural Scientists, as against three originally provided for.

2. The Government of India have further decided that the Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, will be the *ex-officio* Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, All Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Agriculture Secretaries of all the State Governments and Union Territory Administrations, all Attached and Subordinate Offices of the Department of Agriculture, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Parliament Library (5 copies).

The 3rd April 1969

No. 6-45/67-Genl.II.—The Government of India have decided that in the Central Advisory Committee for Agricultural Production set up under their Resolution of even number dated the 22nd December, 1967, and subsequently modified *vide* their Resolutions of even number dated the 27th January, 1968 and 2nd April, 1969, the following persons representing the various interests, shown against them, will be members :—

Thirteen Members of Parliament :

1. Shri Deorao S. Patil, M.P. (Cong.) Lok Sabha.
2. Shri K. N. Tiwari, M.P. (Cong.) Lok Sabha.
3. Shri N. P. C. Naidu, M.P. (Cong.) Lok Sabha
4. Shri Buta Singh, M.P. (Cong.) Lok Sabha.
5. Shri Randhir Singh, M.P. (Cong.) Lok Sabha.
6. Shri K. M. Abraham, M.P. (CPI-M) Lok Sabha.
7. Sardarni, Nirlep Kaur, M.P. (U.A.) Lok Sabha.
8. Prof. N. G. Ranga, M.P. (Swa.) Lok Sabha.
9. Shri Shiv Charan Lal, M.P. (SSP.) Lok Sabha.
10. Shri A. P. Jain, M.P. (Cong.) Rajya Sabha.
11. Shri Jagadambji Prasad Yadava, M.P. (J.S.) Rajya Sabha.

12. Shri Thillai Villalan, M.P. (DMK) Rajya Sabha.

13. Shri N. Sri Rama Reddy, M.P. (Cong.) Rajya Sabha.

Four Leading Progressive Agriculturists :

1. Shri Satwant Singh, Nasirpur Farm, P.O. Bahadurgarh Fort, Patiala.
2. Shri V. G. Sukmaran, President, Kerala State Farmers Forum, Erimayur P.O. District Palghat, Kerala.
3. Shri R. P. Naik, Pusad, District Yeotmal, Maharashtra.
4. Shri Chandrika Ram, M.L.C., Patna, Bihar.

Four Representatives from Agricultural Administrators, Agricultural Economists and Agricultural Scientists :

1. Shri Shah Nawaz Khan, Chairman, Food Corporation of India, New Delhi.—*Agricultural Administrator.*
2. Shri B. Sivaraman, Cabinet Secretary, Government of India, New Delhi.—*Agricultural Administrator*
3. Dr. M. B. Desai, Professor of Agricultural Economics, M.S. University of Baroda, Baroda.—*Agricultural Economist.*
4. Dr. K. Ramiah, Vice Chancellor, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar.—*Agricultural Scientist.*

Three Representatives from non-official Agricultural Institutions and Farmers' Associations :

1. Shri S. B. Pandya, Secretary, National Tonnage Club, F/2, South Extension Part I, New Delhi.
2. Shri S. N. Mushran, Bharat Krishak Samaj, New Delhi.
3. Shrimati Jaya Arunachalam, Joint Secretary, Farmers' Forum, Madras.

Four Representatives of Agricultural Labour :

1. Shri S. Nagappa, ex-M.P., Kurnool, Andhra Pradesh.
2. Shri Gunvanthbhai Purohit, Sanchalak, Sarvodaya Kendra, Babapur, District Amreli, Gujrat.
3. Shri Ramanand Das, ex-M.P., 12 Arpuli Lane, Calcutta.
4. Shri Lahan Choudhry, Convenor of the Bihar Agricultural Labour Committee, Supaul, District Saharsa, Bihar.

2. The term of members other than the *ex-officio* member shall be two years provided that a member shall cease to be such if he ceases to be a member of the body which he represents. All vacancies among members other than the *ex-officio* member shall be filled by the authority which nominated them. A person nominated to a casual vacancy shall continue to be a member of the Committee for the remaining period of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Agriculture Secretaries of all State Governments and Union Territory Administrations, all Attached and Subordinate Offices of the Department of Agriculture, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Parliament Library (5 copies) and all State Governments and U.T. Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. R. PATEL, Secy.

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 3rd April 1969

No. 28(1)/67-CDN(I).—Dr. S. C. Gupta, Director, Agricultural Economics, Research Centre, University of Delhi, and a member of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research of the Indian

Council of Agricultural Research has taken up an assignment under the Food and Agriculture Organisation of the United Nations Organisation for a period of one year with effect from 1st August, 1968. He has thereby under the provisions of Rule 77 read with Rule 11(a) of the Rules of the Council ceased to be a member of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research.

No. 30(3)/69-CDN(I).—Under Rule 34(v) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, Shri G. A. Appan, Member Rajya Sabha, 11-B, Eldams Road, Madras has been selected by the President of the Indian Council of Agricultural Research (Minister of Food and Agriculture) to be a member of the Governing Body of the Society for a period of three years with effect from 24th March, 1969 or till such time as he continues to be member of the Society, whichever period expires earlier.

The 5th April 1969

No. 29(1)/67-CDN.I.—Dr. S. K. Mukherjee, Vice-Chancellor, Kalyani University, P.O. Kalyani, District Nadia, West Bengal, is hereby nominated as a member of the standing Committee for Agricultural Education of the Indian Council of Agricultural Research to represent the University Grants Commission thereon, *vice* Professor V. M. Dandekar, who has resigned, for the period from 24th March, 1969 to 30th July, 1969 or till such time as his successor is nominated on the Committee, whichever period expires earlier.

M. AHMAD, Dy. Secy.

(Department of Community Development)

New Delhi, the 5th April 1969

RESOLUTION

No. 5-1/66-PR.—The need for setting up a national forum reflecting various shades of informed opinion on the subject, to advise the Ministry on suitable policies for promoting the objectives of Panchayati Raj has been recognised. The Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Community Development) *vide* their Resolution No. 14/3/64-PR, dated 12th May, 1964, had constituted a Consultative Council on Panchayati Raj. Its term expired on May 12, 1966.

2. The Council is now hereby reconstituted as under :

(i) Chairman

Union Minister of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.

(ii) Vice-Chairman

Union Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.

(iii) Members

- (1) Union Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.
- (2) Minister for Panchayati Raj, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
- (3) Minister for Community Development, Panchayati Raj and Cooperation, Government of Assam, Shillong.
- (4) Minister in charge of Panchayati Raj, Government of Bihar, Patna.
- (5) Deputy Minister for Animal Husbandry, CD & NES, Government of Jammu & Kashmir.
- (6) Minister for Community Development and Panchayati Raj, Government of Haryana, Chandigarh.
- (7) Minister for Community Development & Panchayati Raj, Government of Gujarat, Ahmedabad.
- (8) Minister for Panchayats and Community Development, Government of Kerala, Trivandrum.
- (9) Minister for Local Administration, Government of Tamil Nadu, Madras.
- (10) Minister for Development and Cooperation, Government of Mysore, Bangalore.

- (11) Minister for Community Development and Panchayati Raj, Government of Maharashtra, Bombay.
- (12) Minister of State for Local Self-Government (Rural) and Panchayati Raj, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
- (13) Minister for Community Development and Panchayati Raj, Government of Orissa, Bhubaneswar.
- (14) Minister in charge of Panchayati Raj, Government of Punjab, Chandigarh.
- (15) Minister for Community Development and Panchayati Raj, Government of Rajasthan, Jaipur.
- (16) Minister in charge of Panchayati Raj, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
- (17) Minister in charge of Panchayati Raj, Government of West Bengal, Calcutta.
- (18) Minister for Panchayati Raj, Government of Himachal Pradesh, Simla.
- (19) Minister for Tuensang Affairs, Community Development & Cooperation, Government of Nagaland, Kohima.
- (20) Member, Planning Commission, in charge of Community Development and Panchayati Raj.
- (21) President of the All-India Panchayat Parishad.
- (22) Chairman, Central Social Welfare Board, New Delhi.
- (23) Shri T. N. Singh, M.P., 16-Ashoka Road, New Delhi.
- (24) Shri Sadiq Ali, M.P., 31-Ferozeshah Road, New Delhi.
- (25) Shri G. S. Reddy, M.P., 135-North Avenue, New Delhi.
- (26) Shri Shashi Bhushan, M.P., 7-North Avenue, New Delhi.
- (27) Shri Ram Krishna Sinha, M.P., 38-Mecna Bagh, New Delhi.
- (28) Shri Biswanarayan Shastri, M.P., 202-South Avenue, New Delhi.
- (29) Shri M. Y. Ghorpade, MLA, Mysore.
- (30) Prof. M. V. Mathur, formerly Vice-Chancellor, Rajasthan University, Jaipur.
- (31) Shri V. R. Radhakrishnan, No. 1-Thiruvvelur, Koil Street, Mylapore, Madras.
- (32) Shri Nettur P. Damodran, Kochu Thope near Aerodrome, Trivandrum, Kerala.
- (33) Shri B. P. Nagarajamurthy, Ragibommanahalli, Malavalli, Taluq, Mandya District, Mysore State.
- (34) Prof. V. M. Dandekar, Gokhale Institute of Politics & Economics, Poona.
- (35) Shrimati Mayadevi Chetty, Kurseong, Darjeeling.
- (36) Shri Hari Kishore Singh, No. 2/15, Srikrishnapai, Patna.
- (37) Prof. M. N. Srinivas, University of Delhi, Delhi.
- (38) Shrimati Jamna Devi, Jhabria, Madhya Pradesh.
- (39) Shri Ganpat Hirulal Bhagat, Nagpur.
- (40) Shrimati Ammanna Raja, Ex-M.P. (Rajya Sabha), Hyderabad.
- (41) Secretary (Agriculture, Community Development & Cooperation), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.
- (42) Additional Secretary (CD), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.
- (iv) Member-Secretary
- (43) Joint Secretary, Department of Community Development, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

3. The functions of the Council will be as follows :—

- (i) To advise the Government on the problems relating to Panchayati Raj and their solution.

(ii) To review, from time to time, the progress and recommend measures for improvements in the implementation of Panchayati Raj in the States, with special reference to the duties cast upon the system and its capacity for performance and identification of problem areas.

(iii) To advise the Government on the measures to be taken to ensure optimum local initiative necessary for the growth and consolidation of Panchayati Raj.

4. The term of office of the members of the Council will be three years.

5. The Council will meet as often as necessary and in any case, at least twice a year. The Council may set up committees as may be required for the efficient discharge of its functions.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

I. D. N. SAHI, Additional Secy.

(Department of Cooperation)

New Delhi, the 28th March 1969

CORRIGENDUM

No. 1-15/68-GOP.—*Read* "Miraj and Sangli Central Co-operative Consumer Stores Ltd. Miraj" for "Miraj and Sangli Shahar Central Cooperative Consumers Wholesale and Retail Stores Ltd. Miraj" at serial No. 17 under Maharashtra of the Schedule published alongwith the Government of India Notification No. 1-25/65-CC, dated 27-5-1966 regarding the Guarantee Scheme for Consumer Cooperative.

S. SATYABHAMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 8th April 1969

RESOLUTION

SUBJECT :—*Setting up of a Conference of Representatives of the Hindi-speaking States for the production of university level books in Hindi and its Coordination Committee.*

No. F.6-44/69-IL-II.—1. The Education Commission (1964-65) recommended that the Indian languages should be adopted as media of education at the university stage. The recommendation was successively approved by the State Education Ministers' Conference (April, 1967), Members of Parliament Committee on Education (July, 1967), and Vice-Chancellors' Conference (September, 1967). The National Policy on Education Resolution (1968) also emphasised the need for adopting Indian languages as the media of education at the university stage. To quote from the Resolution: "The regional languages are already in use as media of education at the primary and secondary stages. Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the university stage."

2. The adoption of Indian languages as media of instruction at the university stage demands production of books in these languages to meet the requirements for the change-over. For this and allied purposes, the Government of India have drawn up a Centrally-sponsored scheme which has been included in the Fourth Five Year Plan with a proposed outlay of Rs. 15 crores. Under this scheme, assistance to the maximum of Rs. 1 crore would be given to each State during the period commencing from 1968-69. During this year, this assistance would be on a sharing basis of 75% by the Centre and 25% by the State Government concerned on the expenditure incurred. In subsequent years, such assistance would be on a 100% basis by the Centre. This decision has been taken by the Government of India on the recommendation of the National Development Council that all Centrally-sponsored schemes from 1969-70 will be on a 100% basis.

3. To implement the scheme, the Ministry of Education prepared a guideline for the formulation of State programmes for the production of university level books in different Indian languages and circulated it to the State Governments. The guideline requires the State Governments to indicate the organisational set-up, the projects undertaken and the manner of the execution of their schemes. In the case of five Hindi-speaking States, it was felt that there was need for coordination in their programmes in order to avoid duplication. Accordingly, the Vice-Chancellors and the Education Secretaries of the Hindi-speaking States and a few other specialists met at Varanasi on 1st and 2nd February, 1968; its main purpose was to work out an effective coordinated national programme for the production of quality books of university level in Hindi in Humanities and Sciences, including Medicine, Engineering and Agriculture. At this Conference, it was resolved that the Standing Committee of the Conference be appointed to coordinate various activities in this field in the Hindi-speaking States. It was further decided by the Ministry of Education that the Commission for Scientific and Technical Terminology will provide the secretariat to the Standing Committee to enable it to discharge its functions as a coordinator.

4. The Standing Committee of the Conference of Vice-Chancellors of the Hindi-speaking States held its first meeting on 24th and 25th May, 1968, at New Delhi, and the second meeting at Patna on 30th October, 1968. The Standing Committee constituted 25 subject panels, consisting of specialists in different subject fields. The subject panels have met and prepared a programme for State Boards to take up 396 books for original writing, 1971 books for translation; and they also approved 812 existing Hindi books on different subjects to be prescribed by the universities.

5. The Standing Committee has thereby given a valuable direction to the programme of production of university level books in Hindi. The Government of India is now of the view that, in order to undertake this work in a manner that will ensure best results, the conference of Vice-Chancellors should be reconstituted on a broader base. Accordingly, the Government of India hereby sets up the Conference of the Representatives of the Hindi-speaking States for the production of university level books in Hindi.

Composition

The Conference will be composed of :—

Chairman

(i) Union Minister of Education & Youth Services.

Vice-Chairman

(ii) Union Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services.

Members

- (iii) Education Ministers of all the Hindi-Speaking States.
- (iv) Chairman of Autonomous Boards or other similar bodies for Book Production in these States.
- (v) Chairman, University Grants Commission.
- (vi) Vice-Chancellors of all the Universities situated in the Hindi-speaking States.
- (vii) Vice-Chancellor, Banaras Hindu University.
- (viii) Vice-Chancellor, Delhi University.
- (ix) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.
- (x) Director, Central Hindi Directorate.

Member-Secretary

- (xi) Joint Secretary, incharge of Languages & Book Production in the Union Ministry of Education & Youth Services.

Functions

The functions of the Conference will be :

- (1) To review generally the progress of book production in all Hindi-speaking States, and
- (2) To advise the Union Ministry of Education and the State Governments on all matters raised before the Conference.

The Coordination Committee

6. Besides the above Conference, the Government of India hereby establishes the Coordination Committee of the Conference.

The composition of this Committee will be :

Chairman

- (i) Union Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services.

Vice-Chairman

- (ii) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.

Members

- (iii) Education Ministers of all the Hindi-Speaking States or their representatives.
 (iv) Chairman, UGC, or his representative.
 (v) Chairman of the autonomous boards or similar bodies for book production in all the Hindi-speaking States or their representatives.
 (vi) One eminent educationist from each Hindi-speaking State to be nominated by the State Government, preferably a Vice-Chancellor.
 (vii) Vice-Chancellor, Banaras Hindu University or his representative.
 (viii) Vice-Chancellor, Delhi University or his representative.
 (ix) Director, Central Hindi Directorate.

Member-Secretary

- (x) Joint Secretary, incharge of Languages and Book Promotion in the Union Ministry of Education & Youth Services.

The functions of this Committee will be :

- (a) to co-ordinate the production programmes of university level books of all the Hindi-speaking States;
 (b) to advise the Union Ministry of Education and the State Government on measures to be taken to avoid duplication of efforts; and
 (c) to work as a clearing house of information.

7. While the Conference will meet once every year, the Coordination Committee may meet every quarter, but not less than twice a year. The Conference and the Coordination Committee will be serviced by the Commission for Scientific and Technical Terminology of the Union Ministry of Education & Youth Services.

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution be communicated to all the Hindi-speaking States, Chairman, University Grants Commission, Vice-Chancellors of all the Universities in the Hindi-speaking States, Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Vice-Chancellor, Delhi University, Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, Director, Central Hindi Directorate, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

New Delhi-1, the 9th April 1969

No. 22/1/69-CAI(2).—In continuation of the Ministry of Education Notification No. 22/1/69-CAI(2) of the 10th March, 1969, Shri B. S. Mathur, Head of the Department of History, University of Udaipur, is appointed as an ordinary Member of the Indian Historical Records Commission in accordance with para 3.I.A(6) of the Government of India Resolution No. 6/25/63-A, 10(C.5), dated the 20th November, 1965, for an unexpired portion of the term expiring on the 3rd April, 1971.

A. S. TALWAR, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 1st April 1969

RESOLUTION

No. DW.11.28(52)/67.—Since Independence the country has made substantial progress in irrigation development. The area under irrigation has been nearly doubled from what it was at the time of Independence. Even so, about four fifths of the country's cultivated area still depends exclusively on rainfall. The drought conditions in the last four years in several parts of the country and the continued food shortages have brought into sharp focus the importance of providing greater irrigation facilities. In this context the maximum exploitation of both surface and ground water resources within the next four to five Plan periods needs greater emphasis and attention. The Government of India have, therefore, decided in consultation with the State Governments and Administrations of Union Territories, to set up an Irrigation Commission to go into the question of future irrigation development in the country in a comprehensive manner. The composition of the Commission shall be as follows :—

Chairman

Shri Ajit Prasad Jain, Member of Parliament.

Vice-Chairman

Dr. S. R. Sen, Additional Secretary, Planning Commission.

Members

Shri O. P. Gupta, Retd. Chief Engineer, Irrigation, Uttar Pradesh.

Another irrigation engineer to be nominated later.

Dr. D. V. Reddy, Extension Commissioner, Department of Agriculture.

Member (part-time)

Shri N. S. Pardasani, Secretary, Irrigation & Power Department, Maharashtra, Bombay.

Secretary

Shri K. S. S. Murthy, Officer on Special Duty, Ministry of Irrigation & Power.

2. The terms of reference of the Commission will be as follows :—

- (1) To review the development of irrigation India since 1903, when the last Irrigation Commission submitted its recommendations, and report on the contribution made by irrigation to increasing the productivity of land and in providing insurance against the vagaries of rainfall.
- (2) To examine in detail the irrigation facilities available in chronically drought affected and food deficit areas and suggest essential and minimum irrigation works to be undertaken promptly in such areas.
- (3) To draw up a broad outline of development of irrigation of all types for achieving self-sufficiency in cereals and for maximising the production of other crops and to make a broad assessment of the funds required for the purpose.
- (4) To examine the adequacy of water supply in major irrigation projects.
- (5) To examine the administrative and organisational set up for the planning, execution and operation of irrigation works, particularly with a view to the speedy completion of projects and reduction of their gestation period.
- (6) To suggest criteria for the sanctioning of irrigation projects; and
- (7) To examine any other matter incidental or related to the development of irrigation in the country and make suitable recommendations.

3. The Headquarters of the Commission will be in New Delhi.

4. The Commission will make its recommendations as soon as practicable but in any case within two years. It may, if it deems fit, submit interim report(s) on any specific problem(s).

5. The Commission will devise its own procedure. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Commission.

6. The Government of India trust that the State Governments/Administrations of Union Territories will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India and all State Governments/Administrations of Union Territories.

K. P. MATHRANI, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

New Delhi-1, the 5th April 1969

(Amendment)

RESOLUTION

No. 7/1/69-FI(NA).—In the Ministry of Information and Broadcasting Resolution No. 7/1/69-FI(NA), dated the 7th February, 1969, regarding National Awards for Films, the following amendments are made :—

- (a) The following shall be inserted after clause (j) of Rule 3.1, namely :

“(k) *Best lyric-writer of the year award :*

A plaque to the author the best film song on the theme of National Integration.

- (b) Clause (k) of Rule 3.1 shall be renumbered as (1).

- (c) The following shall be inserted after the words “screen-play writer/script writer” appearing in the 3rd and 7th lines of the Explanation under Rule 3 :
“lyric-writer”

- (d) Under Rule 10 after the words “best female playback singer” comma and the words “lyric-writer” shall be inserted.

- (e) Under Rule 13 after the words “best screen play writer/script writer” comma and the words “best lyric writer” shall be inserted.

- (f) Under Rule 25 after the words “music director” comma shall be deleted and the words “and lyric-writer” shall be inserted.

- (g) In the schedule to the Rules of the National Awards, the following shall be inserted after S. No. xiii :

“(xiv) Name and full address of the lyric-writer”; and the existing serial numbers (xiv), (xv) and (xvi) shall be renumbered as (xv), (xvi) and (xvii) respectively.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PUBLIC NOTICE

The 7th April 1969

No. 7/12/69-FI(NA).—Government of India have decided that under the scheme for National Awards for Films an award would also be given to the lyric-writer of the best film song of the year on the theme of national integration. The last date for submission of entries of films for the National Awards for films produced during the year 1968 is extended upto April 15, 1969 to enable further entries to be made with reference to this award.

H. B. KANSAL, Under Secy.

